

लोकतंत्र प्रहरी

● वर्ष-01 ● अंक- 276 ● भिलाई, गुरुवार 14 मई 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ संख्या-8 ● मूल्य - 2 रुपया ● संपादक- संजय तिवारी, मो. 920000214

केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी में वृद्धि का निर्णय किसानों के हित में ऐतिहासिक कदम : मुख्यमंत्री

धान सहित 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों को मिलेगा लाभ

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन वर्ष 2026-27 हेतु 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि धान सहित विभिन्न खरीफ फसलों के एमएसपी में की गई उल्लेखनीय वृद्धि यह स्पष्ट करती है कि केंद्र सरकार किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के लिए पूरी



प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में धान के एमएसपी में हुई ऐतिहासिक बढ़ोतरी किसानों के सम्मान, आत्मविश्वास और समृद्धि को नई मजबूती प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए देश में सर्वाधिक 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर रही है।

उन्होंने कहा कि यही कारण है कि प्रदेश में रिकॉर्ड धान खरीदी के साथ किसानों का विश्वास सरकार की किसान हितैषी नीतियों पर लगातार बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार किसान कल्याण, कृषि उन्नति और ग्रामीण समृद्धि के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा कृषि क्षेत्र को नई मजबूती देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार समन्वय के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के हित में लिए गए इस महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया है।

सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी बधाई

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई एवं उज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह उपलब्धि विद्यार्थियों की मेहनत, अनुशासन, समर्पण और निरंतर प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों ने अपने परिश्रम, लगन और आत्मविश्वास के बल पर सफलता की नई मिसाल प्रस्तुत की है, जो अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा में अंक प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की मजबूत आधारशिला है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश के विद्यार्थी आने वाले समय में शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, खेल, कला, अनुसंधान और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ तथा देश का नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करेंगे।

मोदी के किफायत बरतने के आह्वान का देशभर में स्वागत कई मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों ने काफिले का आकार घटाया

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किफायती उपाय अपनाने के आह्वान के बाद अब कई केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों ने अपने आधिकारिक वाहनों की संख्या में कटौती कर दी है।

सरकार के भीतर खर्चों को नियंत्रित करने के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं के काफिले के आकार में काफी कमी की है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वाहनों की संख्या में यह कटौती विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित आवश्यक सुरक्षा प्रबंधों को पूरी तरह सुनिश्चित रखते हुए ही की गई है। सामान्य प्रक्रिया के तहत, प्रधानमंत्री के काफिले में पायलट वाहन, एस्कॉर्ट गाड़ियाँ, प्रधानमंत्री की मुख्य कार, एक बैकअप वाहन, एम्बुलेंस व मेडिकल इमरजेंसी वाहन और एक उच्च तकनीक वाला संचार वाहन शामिल होता है। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने यह निर्देश भी दिया है कि बिना कोई नया वाहन



खरीदी, मौजूदा बेड़े में जहाँ भी संभव हो, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाए। प्रधानमंत्री ने रिवरार को आम नागरिकों से भी ईंधन की खपत कम करने और अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की थी। प्रधानमंत्री की इस अपील का पूरे देश में असर देखा जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने काफिले को वाहनों को काफी कम कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी ईंधन बचाने और सरकारी खर्च कम करने की प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन किया है।

उन्होंने अपने दो दिवसीय महाराष्ट्र दौरे के दौरान अपने आधिकारिक काफिले के आकार को 50 प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री की अपील से प्रेरित होकर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक अनुकरणीय पहल की है। प्रोटोकॉल के तहत उपलब्ध एस्कॉर्ट और पायलट वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद, उन्होंने अपनी कार स्वयं चलाकर यात्रा की। मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या अगले आदेश तक 13 से घटाकर केवल आठ कर दी जाएगी। इसके साथ ही उनके दौरे के दौरान निकलने वाली वाहनों की रैलियों पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

इसी दिशा में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी कड़े निर्देश जारी किए हैं कि सुरक्षा और अन्य आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किसी भी प्रकार के अनावश्यक वाहनों का उपयोग कटौत न किया जाए।

आरसीबी ने केकेआर को छह विकेट से हराया किंग कोहली का नौवां आईपीएल शतक



विराट कोहली का आईपीएल में नौवां शतक

रायपुर। केकेआर पर छह विकेट से जीत के साथ आरसीबी अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई और प्लेऑफ के लिए स्थिति मजबूत कर ली है। बुधवार को रायपुर में खेले गए मुकाबले में केकेआर द्वारा दिए गए 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ा और टीम को जीत दिलाई।

विराट कोहली की तुफानी शतकीय पारी की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु (आरसीबी) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को छह विकेट से हरा दिया। बुधवार को रायपुर में खेले

गए मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर ने अंकुष रघुवंशी की अर्धशतकीय पारी की मदद से 20 ओवर में चार विकेट पर 192 रन बनाए।

जवाब में आरसीबी ने 19.1 ओवर में चार विकेट पर 194 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस दौरान विराट कोहली ने अपने आईपीएल करियर का नौवां आईपीएल शतक पूरा किया। वह 105 रन बनाकर नाबाद रहे। केकेआर के लिए कार्तिक त्यागी ने तीन विकेट लिए जबकि सुनील नरेन को एक सफलता मिली।

विराट कोहली ने 58 गेंदों में अपने आईपीएल करियर का नौवां शतक पूरा कर लिया है। अब आरसीबी को जीत के लिए नौ गेंदों में नौ रनों की जरूरत है।

टिम डेविड आउट हो गए। कार्तिक त्यागी ने उन्हें मनीष पांडे के हाथों कैच कराया। वह सिर्फ दो रन बना पाए। उधर, विराट कोहली शतक के करीब पहुंच गए हैं। वह 99 रन बनाकर ज़ीन पर डटे हैं। 17.5 ओवर में आरसीबी ने चार विकेट पर 180 रन बना लिए हैं। अब बल्लेबाजी के लिए जितेश शर्मा आए हैं।

ट्रम्प ने वेनेजुएला को अमेरिका का 51वां राज्य बताते हुए मानचित्र साझा किया

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक मानचित्र साझा किया है जिसमें वेनेजुएला को अमेरिका के 51वां राज्य के रूप में दिखाया गया है। ट्रम्प ने मजाक में वेनेजुएला को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की ओर संकेत तब दिया जब उन्होंने मानचित्र में विश्व बेसबॉल क्लासिक सेमीफाइनल में



इटली को हराने पर वेनेजुएला की

राष्ट्रीय बेसबॉल टीम को बधाई दी थी। उन्होंने इस जीत का श्रेय मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता (बीडीडीएस) तथा फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में बग से लो-इंटींसिटी विस्फोटक सामग्री तथा बम निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कुछ उपकरण बरामद होने की पुष्टि हुई।

विस्फोटक सामग्री मामले का खुलासा, फरार आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। राजधानी रायपुर में विस्फोटक सामग्री और बम निर्माण से जुड़े संदिग्ध सामान मिलने के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा बुधवार को पुलिस ने किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विनय देवान के रूप में हुई है। मामले में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। पुलिस के अनुसार, खमतराई थाना क्षेत्र के रवभाउर इलाके में एक संदिग्ध बग मिलने की सूचना के बाद गत गुरुवार को इलाके में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता (बीडीडीएस) तथा फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में बग से लो-इंटींसिटी विस्फोटक सामग्री तथा बम निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कुछ उपकरण बरामद होने की पुष्टि हुई।

नई सूची में कई बड़े नेताओं को कोर ग्रुप से बाहर कर दिया गया है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रदेश सरकार में मंत्री रामविवार

नया दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 'नीट-यूजी 2026' पेपर लीक मामले में अपनी जांच तेज कर दी है।

इसी कड़ी में एजेंसी के अधिकारियों की एक टीम परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित विवरण जुटाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के मुख्यालय पहुंची। सूत्रों के अनुसार, पांच सदस्यीय सीबीआई टीम ने एनटीए मुख्यालय का दौरा किया और तीन मई को आयोजित मैकडल प्रवेश परीक्षा से जुड़े कथित लीक

सरकार ने सोने-चांदी के आयात पर शुल्क बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया

नयी दिल्ली। सरकार ने सोने और चांदी के आयात पर शुल्क छह प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। देश में सोने-चांदी की खरीदी को हतोत्साहित करने और इस पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

सूत्रों ने बताया कि सोने और चांदी पर मूल सीमा शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा पांच प्रतिशत कृषि उपकर भी लगाया गया है। इस प्रकार कुल शुल्क 15 प्रतिशत हो गया है। पश्चिम एशिया संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ चुकी है। इस कारण कच्चे तेल और गैस के आयात सरकार को ज्यादा विदेशी



मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है। सरकार दूसरे उपायों का आयात कम कर विदेशी मुद्रा की खपत कम करना चाह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने लोगों से अनावश्यक विदेश यात्रा से बचने और जीवाश्म ईंधनों की खपत कम करने का भी आग्रह किया है। सरकार के कई मंत्री भी प्रधानमंत्री की अपील दोहरा चुके हैं।

सरकार ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी

नयी दिल्ली। सरकार ने सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपये की बड़ी योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपये की बड़ी योजना को मंजूरी दे दी है।

सरकार का कहना है कि यह योजना वर्ष 2030 तक 10 करोड़ टन कोयला गैसीकरण के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य देश की ऊर्जा सुरक्षा



को मजबूत करना और एलएनजी, यूरिया, अमोनिया तथा मेथेनॉल जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम करना है। वर्तमान में भारत अपनी जरूरत का 50 प्रतिशत से अधिक एलएनजी, लगभग 20 प्रतिशत यूरिया, करीब 100 प्रतिशत अमोनिया और 80 से 90 प्रतिशत मेथेनॉल आयात करता है। योजना के तहत लगभग 7.5 करोड़ टन कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण क्षमता

भाजपा कोर ग्रुप का पुनर्गठन:

डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की एंटी, बृजमोहन, रामविवार और गौरीशंकर बाहर

नयी दिल्ली। छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन में बड़ा रणनीतिक बदलाव देखने को मिला है। पार्टी नेतृत्व ने प्रदेश की नई कोर कमेटी का गठन करते हुए वरिष्ठ नेताओं के साथ सरकार के प्रमुख चेहरों को इसमें शामिल किया है।

नई टीम का गठन राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद किया गया। प्रदेश भाजपा की इस अहम निर्णय लेने वाली समिति में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, दोनों उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा के

साथ वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी को भी स्थान दिया गया है। कोर ग्रुप में संगठनात्मक अनुभव रखने वाले नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। इनमें क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश महामंत्री पवन साय, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, नेता लता उसेडी, पूर्व विश्वयुक्त शिवरतन शर्मा और डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी शामिल हैं।

नई सूची में कई बड़े नेताओं को कोर ग्रुप से बाहर कर दिया गया है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रदेश सरकार में मंत्री रामविवार

नया दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 'नीट-यूजी 2026' पेपर लीक मामले में अपनी जांच तेज कर दी है।

इसी कड़ी में एजेंसी के अधिकारियों की एक टीम परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित विवरण जुटाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के मुख्यालय पहुंची। सूत्रों के अनुसार, पांच सदस्यीय सीबीआई टीम ने एनटीए मुख्यालय का दौरा किया और तीन मई को आयोजित मैकडल प्रवेश परीक्षा से जुड़े कथित लीक

पांच सदस्यीय सीबीआई टीम ने एनटीए मुख्यालय का दौरा किया नीट-यूजी पेपर लीक मामले की जांच के लिए सीबीआई पहुंची एनटीए मुख्यालय

नयी दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 'नीट-यूजी 2026' पेपर लीक मामले में अपनी जांच तेज कर दी है।

इसी कड़ी में एजेंसी के अधिकारियों की एक टीम परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित विवरण जुटाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के मुख्यालय पहुंची। सूत्रों के अनुसार, पांच सदस्यीय सीबीआई टीम ने एनटीए मुख्यालय का दौरा किया और तीन मई को आयोजित मैकडल प्रवेश परीक्षा से जुड़े कथित लीक



और अनियमितताओं की चल रही जांच के हिस्से के रूप में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। एजेंसी परीक्षा के संचालन, आंतरिक

वास्तविक पेपर के कई प्रश्नों से काफी हद तक मेल खाता था। सीबीआई पहले ही विशेष जांच दल गठित कर चुकी है और लीक के स्रोत का पता लगाने तथा इस मामले में शामिल व्यापक नेटवर्क की पहचान करने के लिए कई राज्यों में अधिकारियों को भेजा है। अधिकारियों के डिजिटल साक्ष्य, संचार रिकॉर्ड और उस शृंखला की जांच किये जाने की उम्मीद है, जिसके माध्यम से परीक्षा से पहले लीक हुई सामग्री प्रसारित की गयी होगी।

जिनमें कहा गया था कि परीक्षा से पहले प्रसारित एक 'गैस पेपर' से पहले प्रसारित एक 'गैस पेपर'

वनांचल की बेटियों के लिए 2 नई फ्री बसें अब पंडरिया में 10 बसों से शिक्षा को नई उड़ान



कवर्धा। बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने एक और ऐतिहासिक पहल की है। आगामी शैक्षणिक सत्र से वनांचल क्षेत्र कुई-कुंदर एवं कुंड महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ की जाएगी। इस निर्णय के साथ ही पंडरिया विधानसभा में संचालित फ्री बस सेवाओं की संख्या बढ़कर 10 हो जाएगी, जिससे अब तक 1000 से अधिक छात्राएं सीधे लाभान्वित हो चुकी हैं।

वनांचल और दूरस्थ गांवों की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए लंबी दूरी तय करने पड़ती है। कई बार परिवहन सुविधा की कमी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित होती थी। विधायक भावना बोहरा ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए यह संकल्प लिया कि कोई भी बेटा केवल दूरी या संसाधनों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे। इसी सोच के तहत दो नई बस सेवाओं की शुरुआत की जा रही है।

गांव-गांव से महाविद्यालय तक सुरक्षित सफर

कुई-कुंदर महाविद्यालय के लिए बस सेवा काम अमलिया से प्रारंभ होकर केजूर, कुशियारी, कनगाढ़, लुडुटोला, उपका, अमेर और कुकुर की छात्राओं को तेजसे महाविद्यालय पहुंचेगी। वहीं कुंड महाविद्यालय के लिए बस काम पेंडैकला से चलकर बसनी, धोरेपैड़ी, कोलेगांव, कमापुर, खैतपुरवासी, कोयवाकला, पेंडरजली, कुंडीपार, माकरी और खैतपुरवासी की छात्राओं को सुरक्षित महाविद्यालय तक पहुंचाएगी। यह सेवा न केवल आकांक्षित की सुविधा देगी, बल्कि छात्राओं और उनके परिवारों में सुरक्षा और विश्वास की भावना भी मजबूत करेगी। अब बेटियां बिना किसी डर और आर्थिक बोझ के शिक्षा की राह तय कर सकेंगी।

पूर्व की 8 बस सेवाएं भी जारी

विधायक भावना बोहरा द्वारा प्रारंभ की गई 8 निःशुल्क बसें वनांचल की जा रही हैं, जो यथावत चल रही हैं। बसों के जुड़ने से पंडरिया विधानसभा में कुल 10 बसें छात्राओं की सेवा में रहेंगी। इस पहल का उद्देश्य अंतर भी समाने अब है। क्षेत्र में छात्राओं की उपस्थिति पर नजर रखी जा रही है और अधिक से अधिक बेटियों को उच्च शिक्षा तक पहुंचाया जा रहा है।

पंजीयन जून से, संपर्क नंबर जारी

निःशुल्क बस सेवा का लाभ लेने के लिए पंजीयन प्रक्रिया आगामी जून माह से शुरू होगी। छात्राएं अपने नजदीकी जनसेवा ही भावना सेवा सुविधा केंद्र (विधायक कार्यालय) से पंजीयन फॉर्म प्राप्त कर उसे भरकर जमा करेंगी। सत्यापन के बाद उन्हें पहचान पत्र जारी किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए छात्राएं एवं उनके परिवार में मोबाइल नंबर 9754462000 और 9755359004 पर संपर्क कर सकते हैं। बसों की समय-सारिणी भी तय कर ली गई है, जिसको विस्तृत सूचना शीघ्र जारी की जाएगी।

शिक्षा ही भविष्य की नींव

इस अवसर पर विधायक भावना बोहरा ने कहा कि बेटियों की शिक्षा ही समाज के उज्वल भविष्य की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि जल्दी प्राथमिकता है कि पंडरिया विधानसभा की हर बेटा आभारिणी बने और अपने परिवार, समाज एवं प्रदेश का नाम रोशन करे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री कृष्णमोहन शर्मा के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सकारात्मक कार्य हो रहे हैं। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए पंडरिया विधानसभा में शिक्षा, सुरक्षा और सुविधा को एक साथ मजबूत किया जा रहा है।

केवल बस नहीं, समग्र विकास का अभियान

विधायक भावना बोहरा द्वारा क्षेत्र में 8 निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा, मोबाइल हेल्थ पैथ लैब, टयूरुट में पंडरिया सेवा केंद्र, लक्ष्य निःशुल्क कॉफिंग और शिक्षा जलसुविधा केंद्रों के अभाव से भी जनता को सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं। उल्लेख है कि यह पहल केवल एक परिवहन व्यवस्था नहीं, बल्कि वनांचल क्षेत्र की बेटियों को नई शिक्षा देने वाला सशक्त कदम है। उप-पंडरिया विधानसभा में दूरी बाधा नहीं, बल्कि अवसर बस चुकी है—और सड़कों पर चौराहों ये बसें बेटियों के सपनों को नई उड़ान दे रही हैं।

कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं 88 आवेदन प्राप्त



बेमेतरा। जिले में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाले जनदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्टर के जनदर्शन का आयोजन किया गया। जनदर्शन में कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठ ममगाई ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। जनदर्शन के दौरान नागरिकों ने अपने विभिन्न मांगों, शिकायतों एवं समस्याओं को प्रशासन के सम्पर्क रखा। कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठ ममगाई ने प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशीलता के साथ संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को दृष्टांतर पर एवं समक्ष बुलाकर प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। कई प्रकरणों का समाधान मौके पर ही किया गया। जनदर्शन में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 88 आवेदन प्राप्त हुए। तात्कालिक महत्व के मामलों का प्राथमिकता से निराकरण किया गया, जबकि गंभीर एवं जांच योग्य आवेदनों को समय-समय (टोएल) पंजी में दर्ज कर नियमानुसार शीघ्र निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। जनदर्शन में निराश्रित एवं वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, बैटरी चालित ट्रायसाइकल, प्रधानमंत्री आवास योजना, कटा हुआ रकबा जोड़ने, खाद गन्ना हटाने, आम रास्ता खुलवाने सहित अन्य जनहित से जुड़े विषयों पर आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने सभी आवेदकों को उनकी समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।

सांस्कृतिक मंच एवं महाकाल द्वार हेतु भूमिपूजन नपअध्यक्ष निधि एवं पार्षद निधि से होगा निर्माण

डोंगरगांव नगर। नगर के मंडियावाड़ क्र 14 स्थित द्वारश शिवमंदिर परिसर में स्थित महिला भवन प्रांगण में सांस्कृतिक मंच एवं मेगनेट महाकाल द्वार का निर्माण सुनिश्चित हो गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष निधि एवं वार्ड 14 के पार्षद निधि से होने वाले उक्त निर्माण हेतु मंगलवार को भूमिपूजन किया गया। उल्लेखनीय है कि सांस्कृतिक मंच निर्माण हेतु नगर पंचायत अध्यक्ष निधि से 2 लाख एवं वार्ड 14 के पार्षद निधि से 3 लाख की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं परिसर में निकस पट से महाकाल द्वार नाम से मेन गेट का निर्माण भी किया जा रहा है। भूमिपूजन अवसर पर सांसद



प्रतिनिधि लक्ष्मीनारायण गुप्ता, नप अध्यक्ष अंशु त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष दीना पटेल, पूर्व उपाध्यक्ष गुलशन हिक्वाना, वार्ड 14 पार्षद व सभापति पुरुषोत्तम साहू, कृष्णकुमार शर्मा,

कलेक्टर द्वारा आठ प्राचार्यों का निलंबन व चौदह प्राचार्यों का वेतन-वृद्धि रोकने का शिक्षक संघ ने किया विरोध

दल्लीराजहरा। बालोद जिला कलेक्टर के द्वारा आठ प्राचार्यों का निलंबन व चौदह प्राचार्यों का वेतन-वृद्धि रोकने का छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ पुरजोर विरोध करता है। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के संभागीय अध्यक्ष भुवन सिन्हा ने शिक्षा मंत्री व सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर बालोद जिला में कलेक्टर द्वारा की गई कार्यवाही पर विरोध व असंतोष जताया है। परीक्षा परिणाम में गिरावट के नाम पर प्राचार्यों के विरुद्ध कलेक्टर द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना सिविल सेवा नियमों के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण)नियम 1965 और नियम 1966 के नियम 9 अनुसार द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का अधिकार केवल राज्य सरकार को ही है। उल्लेखनीय है कि प्राचार्य द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी हैं। केवल परीक्षा परिणाम में गिरावट को गंभीर कटाघात मानकर सीधे अनुशासनात्मक कार्यवाही करना प्राकृतिक न्याय के खिलाफ भी है। इस प्रकार अपने क्षेत्राधिकार से बाहर व अनाधिकार

कार्यवाही से शिक्षकों में जहां एक ओर आक्रोश है वहीं दूसरी ओर शैक्षणिक अमले में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रहा है जो भविष्य में शैक्षणिक वातावरण के लिए हानिकारक है। परीक्षा परिणाम में गिरावट के लिए केवल प्राचार्यों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। जिले भर में परीक्षा परिणाम में गिरावट के लिए क्या जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी जिम्मेदार नहीं हैं। वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था छात्रों और शिक्षकों की योग्यता का आंकलन केवल परीक्षा परिणाम तक ही सीमित हो गया है जो शिक्षा का मानक मापदंड नहीं होना चाहिए। सिन्हा ने अपने पत्र में सचिव स्कूल शिक्षा विभाग से आग्रह किया है कि भविष्य में जिला प्रशासन को विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध सीधे कार्यवाही से बचने का स्पष्ट निर्देश जारी किया जाए। माननीय न्यायालय ने ऐसे अनेक मामलों में टिप्पणी कर कलेक्टर द्वारा की गई कार्यवाही को रद्द कर चुका है। कलेक्टर बालोद द्वारा जिले में विभागीय व विचार के नाम देते वला आदेश निरस्त कर शिक्षकों का सम्मान को बहाल किया जाए।

सेजेस सिंघौरी में पारदर्शिता पूर्ण लॉटरी प्रक्रिया सम्पन्न



बेमेतरा। सेजेस सिंघौरी के प्रांगण में आयोजित लॉटरी प्रक्रिया आज दिनांक 12 मई 2026 को सफरतापूर्वक संपन्न हुई। यह प्रक्रिया सुबह 8.00 बजे से शाला विकास समिति के अध्यक्ष टी.डी. मोनिकपुरी जी एवं सदस्यगण, नौतू कोटारी (पार्षद) साथ ही साथ पालक गण उपस्थित रहे। संस्था के प्राचार्य संजय प्रसाद प्यासी जी एवं स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति में पूरी पारदर्शिता के साथ की गई। सभी टिकटों को उपस्थित लोगों के सामने मिलाया गया और ड्रॉ बॉक्स से विजेता टिकट निकाले गए। इस लॉटरी प्रक्रिया में नाम आए छात्र/छात्राओं को अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ 15 दिनों के भीतर ऐडमिशन के लिए विद्यालय में संपर्क करें। पूरी विजेता सूची का कार्यालय में सूचना पटल पर चमस कर दी गई है। लॉटरी प्रक्रिया में विद्यालय के व्याख्याता श्री राम गोपाल चंद्रकर जी, विनोद कुमार साहू व्याख्याता, माधुरी साहू व्याख्याता, समीर कुमार व्याख्याता, तुषार कुमार व्याख्याता, अनिल कुमार शिक्षक, वेदिका साहू शिक्षक, आशीष तिवारी सहित विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षकीय की गरिमायम उपस्थित रहें।

जिले में 01 जनपद पंचायत सदस्य, 2 सरपंच एवं 21 पंच पदों के लिए होगा उप निर्वाचन

बेमेतरा। त्रिस्तरीय पंचायत अंतर्गत जिले में रिक 01 जनपद पंचायत सदस्य, 02 सरपंच एवं 21 पंच पदों के उप निर्वाचन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 11 मई 2026 को निर्वाचन संबंधी सूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। कार्यक्रम जारी होते ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण सहिता प्रभावशाली हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बेमेतरा सुश्री प्रतिष्ठ ममगाई द्वारा पंचायत उप निर्वाचन के सुचारु संचालन हेतु संबंधित खण्ड मुख्यालयों के तहसीलदारों को रिटर्निंग आर्गिसर तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सहायक रिटर्निंग आर्गिसर नियुक्त किया गया है। ये अधिकारी आयोग के निर्देशानुसार नाम निर्देशन पत्र प्राप्त से लेकर निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक सभी दायित्वों का निर्वहन करेंगे। जिले के विकासखण्ड बेरला अंतर्गत जनपद पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 07 रिक्त है, जिसमें ग्राम पंचायत रेवे, भरचट्टी, पतौरा एवं सिलफट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत सुरहोली में सरपंच पद तथा ग्राम पंचायत कोदवा वार्ड क्रमांक 04, कंठला वार्ड क्रमांक 08, बावनलाख वार्ड क्रमांक 09 एवं भरदा वार्ड क्रमांक 03 एवं 10 में पंच पद रिक्त हैं। विकासखण्ड साजा में ग्राम पंचायत अरायनगर के वार्ड क्रमांक 03 एवं ग्राम पंचायत सोमईखुई के वार्ड क्रमांक 01 में पंच पद रिक्त हैं। वहीं विकासखण्ड नवागढ़ के ग्राम पंचायत बोटेबोड में सरपंच तथा ग्राम पंचायत मुस्ता वार्ड क्रमांक 15 एवं अतरगांव वार्ड क्रमांक 10 में पंच पदों पर उप निर्वाचन करया जाएगा। इसी प्रकार विकासखण्ड

बेमेतरा के ग्राम पंचायत पथरां के वार्ड क्रमांक 04, 06, 07, 09, 10, 11 एवं 13, ग्राम पंचायत रामपुर वार्ड क्रमांक 07, ग्राम पंचायत बेतर वार्ड क्रमांक 08, ग्राम पंचायत दुड्ड वार्ड क्रमांक 04, ग्राम पंचायत बंधी वार्ड क्रमांक 05 एवं ग्राम पंचायत भोईनामाडा वार्ड क्रमांक 04 में रिक्त पंच पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित पदों हेतु निर्वाचन की सूचना, आरक्षण संबंधी जानकारी एवं मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन विहित प्रारूप में 11 मई 2026 को किया गया है। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य जनपद पंचायत कार्यालयों में प्रतिदिन पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 18 मई 2026 निर्धारित की गई है।

ग्राम धिवरी में समाधान शिविर आज

बेमेतरा। सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत 13 मई को जनपद पंचायत बेमेतरा के ग्राम पंचायत डोलिया (शास. पूर्व मा. शाला) में समाधान शिविर आयोजित किया गया है। ग्राम मोहतरा टिक, लावातारा, घनागांव, अतरिया, मरका, झालम, झाल, केवाडी, चारपाठ, डोलिया, बिल्ड, पंडरमठ, पेंडरीतराई, नरी, मूलमुला, खाम्ही, बागडेरा, चदन, मुटपुरी एवं केशतरा ग्राम पंचायत के लिए यह शिविर आयोजित किया गया है, इसी प्रकार विकासखण्ड साजा के ग्राम पंचायत धिवरी (शास. हाई स्कूल) में समाधान शिविर आयोजित किया गया है। ग्राम खुरुलबोड आर, सैगोना, कारोसर, गर, धिवरी, सौरी, छातो,

हरदास डगनिया, पतौरा हाटराका बरगा केशतरा, गडुवा, खैरझिटी कला, हथमुडी, पदमी, पदुमसरा एवं किरकी ग्राम पंचायत के लिए यह शिविर आयोजित किया गया है, इसी प्रकार नगर पालिका पंचायत बेमेतरा में वार्ड क्रमांक 01 से 07 बेसिक ग्राउण्ड गांधी भवन वार्ड 04 बेमेतरा में यह शिविर आयोजित किया गया है। शिविर का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 03 बजे निर्धारित किया गया है। समाधान शिविर में विभिन्न योजनाओं से प्राप्त अनेक हितप्राप्तियों को विभागीय योजनाओं से लाभांशित किया जाएगा। शिविर में प्राप्त आवेदनों का यथासंभव निराकरण किया जाएगा।

सुशासन तिहार में सांसद भोजराज नाग का फूटा गुस्सा, अधिकारियों को बोले: जनता को गुमराह किया तो उल्टा टांग दूंगा

पीएचई, राजस्व, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग पर बरसे सांसद, गलत आंकड़े पेश करने पर अफसरों को चेतावनी

बालोद। जिले के गुंडरदेही विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम मंडिया में आयोजित सुशासन तिहार के जनसमस्या निवारण शिविर में मंगलवार को उस समय माहौल पूरी तरह गरमा गया, जब कांग्रेस लोकसभा सांसद भोजराज नाग अधिकारियों की कार्यशैली और लंबित मामलों के निराकरण को लेकर मंच से



ही भड़क उठे। ग्रामीणों की शिकायतें सुनने के बाद सांसद ने पीएचई विभाग, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन सहित कई अधिकारियों को खुले मंच से जमकर क्लाम लगाई। शिविर में मौजूद ग्रामीणों ने पेयजल, अचूरी निर्माण कार्य, जल जीवन मिशन,

राजस्व प्रकरण और प्रशासनात्मक लापरवाही से जुड़े शिकायतों की झड़ी लगा दी। शिकायतों और विभागीय आंकड़ों में भारी अंतर सामने आने पर सांसद भोजराज नाग का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है, लेकिन कुछ अधिकारी इसे केवल खानापूर्ति बनाकर सरकार को छवि खराब कर रहे हैं। इस दौरान गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद, जिला पंचायत अध्यक्ष तारणी चन्द्राकर, कलेक्टर दिवा मिश्रा, जिला पंचायत सईईओ सुनील चंद्रवर्ती सहित क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

कहा 'जनप्रतिनिधि और ग्रामीण यहां भविष्य रखने नहीं आए हैं। लोग सरकार की योजनाओं का लाभ लेने आए हैं। अंतर्गत और के व्यक्तिक तर्क योजनाएं पहुंचनी चाहिए। अगर सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिश हुई तो बर्दाश्त नहीं करेगा।' सांसद के सख्त लेखर और तीखी फटकार के बाद शिविर में मौजूद अधिकारियों में हड़कप की स्थिति देखने को मिली। ग्रामीणों ने भी सांसद के सख्त उखर का समर्थन करते हुए कहा कि पहली बार उज्ज्वी उपस्थितियों को लेकर किसी जनप्रतिनिधि ने खुलकर आवाज उठाई है।

3 साल से भटक रहे बुजुर्ग की पीड़ा सुन बढ़के सांसद

शिविर के दौरान 70 वर्षीय परदेशी राम साहू ने सांसद भोजराज नाग को बताया कि वे पिछले तीन वर्षों से राज्य सरकार को लेकर परेशान हैं और तहसीलदार कार्यालय के चक्कर खा रहे हैं, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। यह सुनते ही सांसद मंच पर मौजूद गुंडरदेही परदेशी पर भड़क उठे और तीखे अंशज में कहा 'अधिकारी राज चला रहे हो क्या? जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे शिविर लगाने का क्या मतलब, जिसमें सिर्फ गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं...?' सांसद ने अधिकारियों को

सबसे ज्यादा बजट लेकर भी रिजल्ट जीरो, शिक्षा विभाग पर भी बरसे सांसद

सांसद भोजराज नाग ने शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा विभाग को सबसे अधिक बजट देती है, लेकिन परिणाम बेहद निराशाजनक हैं। उन्होंने मंच से कहा 'सबसे ज्यादा बजट दिया है और परिणाम देखो तो जीरो। मुझे बहुत दुख हुआ। कई लोगों ने फोन कर कहा कि सिर्फ बजट के भूत उबारोगे, क्या बालोद जिले का नहीं...?' सांसद के इस बयान के बाद कार्य म स्थल पर मौजूद अधिकारी भी अस्थिर नजर आए।

अधूरी पानी टंकी और स्वास्थ्य केंद्र पर भी फूटा गुस्सा

राम पंचायत शिवी के सड़क सुकील बेल्बंदन और बधेनी के सड़क उभेबट रेलवे की भी जल जीवन मिशन के अचूरी कार्य की शिकायत सांसद से की। शिवी सड़क के बाया कि गंव में फनी टंकी का निर्माण अचूरी है और अब एक टंकी तक पानी भी नहीं पहुंच रहा है। वहीं सीपीएमएसटी के अध्यक्ष से बन रहे उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण भी अचूरी पड़ा है, जबकि शिविर में उखर निराकरण होना बा दिया गया। इस पर सांसद ने सीपीएमएसटी को फटकार लगाते हुए कहा 'जब काम अचूरी है तो सत-प्रतिष्ठ निराकरण क्यों बात रहे हो? लंबित है तो लंबित बताओ। हडिथिटी मत आते।'

शिविर के दौरान सांसद जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की जांचकरी ले रहे थे। इस दौरान पीएचई विभाग ने बताया कि शिक्षा को प्राप्त 50 आवेदनों का सत-प्रतिष्ठ निराकरण कर दिया गया है। लेकिन मौके पर मौजूद ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने शिक्षा के बावों की पोल खोल दी। कई ग्रामीणों ने बताया कि समस्याओं का समाधान अब तक हुआ ही नहीं है और शिक्षाकांक्षियों में निराकरण दिखाया गया है। इस पर सांसद भोजराज नाग पीएचई विभाग के ईई पर अंगभक्त हो गए। उन्होंने अधिकारियों पर जनता को गुमराह करने और

पीएचई विभाग सांसद के निशाने पर, जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का आरोप

झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप लगाते हुए कहा 'जब समस्याओं का समाधान करना ही नहीं था तो शिविर लगाने का क्या मतलब है...?' गुस्से में सांसद ने यहां तक कह दिया 'ऐसे अधिकारियों को उल्टा लटकना बना चाहिए।' सांसद की इस तीखी टिप्पणी के बाद कार्य म स्थल पर कुछ देर के लिए सन्नत छा गया। सांसद भोजराज नाग ने मंच से घोषण करते हुए कहा कि वे स्वयं गांवों में जाकर जल जीवन मिशन के कार्यों की जांच

करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मौके पर गड़बड़ी मिली तो जिम्मेदारों पर सख्त कार्यवाई कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सेवा के लिए अधिकारियों को वेतन देती है, इसलिए आम लोगों को प्रकरतों के चक्कर खाकर वेतन बंद करे। अपने संबोधन के दौरान सांसद भोजराज नाग ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि सभी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करें। उन्होंने

रेत से भरे 02 वाहन एवं मुरुम उत्खनन में संलिप्त 1 जेसीबी जल



बेमेतरा। अवैध खनन उत्खनन एवं परिवहन पर लगातार सख्त कार्यवाई की जा रही है। इसी क्रम में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा 09 मई 2026 से 11 मई 2026 तक विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण एवं जांच अभियान चलाया गया। खनिज विभाग की टीम द्वारा ग्राम कड़का एवं चन्दरु क्षेत्र में अवैध रूप से रेत परिवहन करते पाए जाने पर 02 वाहनों को जप्त किया गया। वहीं ग्राम बिरनपुर में अवैध मुरुम उत्खनन करते पाए जाने पर 01 जेसीबी वाहन को भी जप्त कार्यवाई की गई। जप्त वाहनों के विरुद्ध खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 से 23-ख के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। अवैध रेत परिवहन के 02 प्रकरणों में कुल 57 हजार रुपये अर्थहण्ड को कार्यवाई की जाएगी। वहीं अवैध मुरुम उत्खनन से संबंधित प्रकरण में नियमानुसार आगे की कार्यवाई प्रक्रियाधीनी है।

संक्षिप्त समाचार

पुरानी रजिस्ट्रार में खूनी हमला, बटनदार चाकू के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। बिलासपुर नूतन चौक में पुरानी दुश्मनी ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, गाली-गलौज से शुरू हुआ विवाद चाकू और जानलेवा हमले तक पहुंच गया सरकंडा पुलिस ने मारपीट और अवैध हथियार रखने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। मामला नूतन चौक का है, जहां 3 मई 2026 को सुबह प्रार्थी प्रियांशु शुक्ला अपने साथियों के साथ 'अपना मार्ट' के पास खड़ा था। इसी दौरान पुरानी रजिस्ट्रार को लेकर आरोपी राजा यादव अपने साथियों लिल्ली नाई और बंदकू यादव के साथ वहां पहुंचा और देखते ही देखते गाली-गलौज शुरू कर दी। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने हाथ-मुकों से मारपीट शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी देने लगे। हमले में प्रार्थी के साथी युवराज पाण्डेय को गंभीर चोट आई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की शिकायत पर थाना सरकंडा में अपराध क्रमांक 617/2026 दर्ज कर धारा 296, 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस और 25, 27 आरएम एक्ट के तहत मामला कायम किया गया। मामले को गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर आरोपियों को तलाश शुरू की। विवेचना के दौरान मुख्य आरोपी राजा यादव पिता विनोद यादव, उम्र 21 वर्ष, निवासी अटल आवास नूतन चौक थाना सरकंडा को हिरासत में लेकर पुछताछ की गई, जहां उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक स्टील का धारदार बटनदार चाकू बरामद कर जब्त किया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, जबकि मामले में शामिल अन्य पक्ष आरोपियों को तलाश सरगर्मा से जारी है। पुलिस को इस त्वरित कार्रवाई के बाद क्षेत्र के असाधारण तत्वों में भय का माहौल है और स्थानीय लोगों ने पुलिस की सक्रियता की जमकर सराहना की है। बहरहाल, बिलासपुर पुलिस का साफसंदेश है कि रजिस्ट्रार के नाम पर हथियारबाजी और गूंडागर्दी करने वालों को अब सीधे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।

भीषण गर्मी में राहत हैंडपंप मरम्मत से ग्रामीणों को मिली सुविधा

रायपुर। भीषण गर्मी और बढ़ते जल संकट के बीच लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग को टीम द्वारा विकासखंड भरतपुर के ग्राम बड़गांवकला, घाटमा, केसीडा, जनीरा एवं दाबनुमाड़ी में हैंडपंपों को मरम्मत और निरीक्षण कार्य किया गया। गर्मी के मौसम में पेयजल की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए खराब एवं बंद पड़े हैंडपंपों को प्राथमिकता के आधार पर सुधार कर पुनः चालू किया जा रहा है। विभागीय अमले को तत्परता से ग्रामीणों को समय पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है, जिससे उन्हें काफी राहत मिली है। ग्रामीणों ने प्रशासन एवं विभागीय टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि समय पर मरम्मत कार्य होने से पानी की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। विभाग द्वारा लगातार गांवों का निरीक्षण कर पेयजल व्यवस्था पर निगरानी रखी जा रही है, ताकि भीषण गर्मी के दौरान किसी भी क्षेत्र में जल संकट उत्पन्न न हो। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने बताया कि जिले भर में हैंडपंप सुधार एवं रखरखाव का कार्य निरंतर जारी है और जहां से भी खराब हैंडपंप को सूचना प्राप्त हो रही है, वहां तत्काल टीम भेजकर समस्या का समाधान किया जा रहा है।

झोराघाट में पुलिस का ताबड़तोड़ एवशन, 23 बाइक चालकों पर चालानी कार्रवाई से हड़कंप

रायपुर। पिकनिक स्पॉट पर फर्स्टबाजी, स्टैंट और शराब के नशे में दीड़ रही बाइकों पर आखिरकार पुलिस का टंडा चल गया कटघोरा पुलिस ने 'सजग कोरबा, सतर्क कोरबा' अभियान के तहत झोराघाट पिकनिक स्पॉट में ऐसा सघन वाहन जांच अभियान चलाया कि नियम तोड़ने वाले बाइक चालकों में अफ़ा-तपसी मच गई। रविवार 10 मई 2026 को झोराघाट पिकनिक स्पॉट में बड़ी संख्या में लोग परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पहुंचे थे, इसी दौरान कई युवक तेज रफ़्तार, बिना सायलेंसर, तीन सवारी बैठाकर और स्टैंटबाजी करते हुए फर्स्ट भरते नजर आए, जिससे आम लोगों और पर्यटकों की सुरक्षा खतरों में पड़ गई। मामले को गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर सघन वाहन चेकिंग शुरू की। अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने, तेज रफ़्तार से बाइक दौड़ाने, बिना सायलेंसर बाइक चलाने और तीन सवारी बैठाकर नियम तोड़ने वाले युवकों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। पुलिस ने कुल 23 दोषीय वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए जुर्माने वसूला। अचानक हुई कार्रवाई से स्टैंटबाजी और नियम तोड़ने वालों में हड़कंप मच गया, कई बाइक चालक पुलिस को देखते ही रास्ता बदलते दिखाई दिए। पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटेल, नीतीश ठाकुर और एसडीओपी विजय सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में अंजाम दी गई। थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी ने साफचेतावनी दी है कि सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कोमत पर बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी सार्वजनिक स्थलों व मुख्य मार्गों पर लगातार वाहन जांच अभियान चलता रहेगा। पुलिस ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें, अन्यथा वाहन मालिक और परिवारों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस कार्रवाई की जमकर सराहना की है और कहा है कि ऐसे अभियान से दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी और यातायात नियमों को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। बहरहाल, कोरबा पुलिस का साफसंदेश है कि सड़क को स्टैंट का मैदान बनाने वालों के लिए अब हर मोड़ पर कानून तैयार खड़ा है।

20 मई को दवा दुकानें रहेंगी बंद, दवा विक्रेताओं ने सरकार को सौंपा ज्ञापन

रायपुर। जिला दवा विक्रेता संघ रायपुर ने 20 मई को प्रस्तावित एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी दवा व्यापार बंद की घोषणा की है। इस संबंध में संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर औषधि व्यापार और जनस्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर हस्तक्षेप की मांग की है। संघ के अध्यक्ष विनय कुपलानी और सचिव संजय रावत ने बताया कि यह बंद ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़ केमिस्ट्स एंड ड्रुगिस्ट्स के आह्वान पर किया जा रहा है। संगठन देशभर के 12.40 लाख से अधिक केमिस्ट और दवा विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करता है। दवा विक्रेताओं ने प्रदेशभर में औषधि विभाग द्वारा चलाए जा रहे पखवाड़े भर के जांच अभियान पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि लगातार कार्रवाई और नियमों के दबाव से छोटे व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

नारायणपुर में जनसमस्या निवारण शिविर बना जनसेवा का प्रभावी माध्यम

खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं किया निराकरण

योजनाओं से अनेक हितग्राही हुए लाभान्वित रायपुर/ संवाददाता

शासन की संशानुसार आम जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से बेमेतरा जिले के ग्राम नारायणपुर में विशाल जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं और मांगें लेकर पहुंचे। यह शिविर ग्रामीणों के लिए अपनी लंबित समस्याओं के समाधान का एक प्रभावी मंच साबित हुआ। कार्यक्रम को मुख्य विशेषता प्रदेश के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल की गरिमामयी उपस्थिति रही। मंत्री श्री बघेल ने स्वयं शिविर में पहुंचकर आमजनों की समस्याएं सुनीं तथा विभागीय अधिकारियों से आवेदनों के निराकरण की

स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आम जनता की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। खाद्य मंत्री श्री बघेल ने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों से आत्मीय संवाद करते हुए उनकी समस्याओं, मांगों और आवश्यकताओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। मंत्री श्री बघेल ने कहा कि शासन का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने विभागों की योजनाओं, सेवाओं एवं कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। उन्होंने ग्रामीणों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं से प्रशासन को अवगत कराएं। शासन समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण एवं उत्थान के



लिए निरंतर कार्य कर रहा है। शिविर में राजस्व, कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। इन स्टॉलों के माध्यम से ग्रामीणों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया। शिविर में राशन कार्ड निर्माण, पेंशन प्रकरण, सीमांकन एवं अन्य जनसमस्याओं से संबंधित कई

मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया। त्वरित समाधान मिलने से ग्रामीणों के चेहरों पर संतोष एवं खुशी स्पष्ट दिखाई दी। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के शिविरों से उन्हें सीधे राहत मिल रही है। कार्यक्रम के दौरान खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालय के पांच विद्यार्थियों को 10-10

हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर सम्मानित किया। मंत्री श्री बघेल ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा ही उच्चतर बर्तव्य का आधार है और मेहनत व लगन से विद्यार्थी जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। शिविर के दौरान ग्राम पंचायत नारायणपुर के सरपंच द्वारा ग्राम में सीसी रोड निर्माण की मांग रखी गई, जिस पर मंत्री श्री बघेल ने ग्राम पंचायत में सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए 10 लाख रुपए रवीकृत करने की घोषणा की। इस घोषणा से ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखा गया। शिविर को संबोधित करते हुए मंत्री श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जनसमस्या निवारण शिविरों के माध्यम से प्रशासन को सीधे जनता के द्वार तक लाया गया है, ताकि ग्रामीणों को अपने जायज कार्यों के लिए दफ्तरों के चकर न लगाने पड़ें।

सुकमा में सिंगल विंडो सुविधा से ग्रामीणों के जीवन में आई सुशासन की बहार.....

अब दफ्तरों के चक्करों से मिली मुक्ति, मिनटों में बन रहे राशन, आधार और आयुष्मान कार्ड

रायपुर/ संवाददाता

अब दफ्तरों के चक्करों से मिली मुक्ति, मिनटों में बन रहे राशन, आधार और आयुष्मान कार्ड। सिंगल विंडो (एकल खिड़की) प्रणाली और डिजिटल गवर्नेंस के संयोजन ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन और ईव ऑफ लिविंग (जीवन सुगमता) में युगांतरकारी परिवर्तन लाए हैं। यह पहल ग्रामीण

आबादी को प्रशासनिक जटिलताओं से मुक्त कर सीधे विकास से जोड़ रही है। पहले छोटे-छोटे कार्यों के लिए ब्लॉक या जिला मुख्यालयों के चक्र कराने पड़ते थे, लेकिन अब सिंगल विंडो के माध्यम से यह प्रक्रिया घर के पास या ऑनलाइन हो गई है। छत्तीसगढ़ के सुदूर बर्नाचल जिला सुकमा में प्रशासन को सिंगल विंडो व्यवस्था ने जनसेवा की नई इबारत लिखी है। कलेक्ट्रेट परिसर में संचालित इस अनूठी सुविधा ने दूरस्थ गांवों के ग्रामीणों को राह आसान कर दी है। अब ग्रामीणों को अपने जरूरी शासकीय दस्तावेजों के लिए अलग-अलग कार्यालयों की दौड़ नहीं लगानी पड़ती, बल्कि एक ही छत के नीचे उनकी सभी समस्याओं का त्वरित निराकरण हो रहा है। इस जन-



हितपी व्यवस्था का शुभारंभ सुकमा जिले में प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप द्वारा किया गया था। तब से यह केंद्र आम नागरिकों के लिए रश्मिसे का केंद्र बन चुका है। यहाँ राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे महत्वपूर्ण सेवाएं बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराई जा रही हैं। पुनर्वास केंद्र से आई मुचाकी देवे इस बदलाव की प्रत्यक्ष गवाह

हैं। उन्हें सिंगल विंडो केंद्र में तत्काल नया राशन कार्ड प्रदान किया गया। मुचाकी ने खुशी जाहिर करते हुए बताया, पहले एक कार्ड के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज यहाँ चंद्र मिनटों में मेरा काम हो गया। उनके साथ आए अन्य नागरिकों को भी तत्काल आधार और आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधाएं प्रदान की गईं। जिला मुख्यालय सुकमा से 41 किमी दूर मेकवावा गांव की कवासी रेशमा ने अपनी सफरता की कहानी साझा करते हुए बताया कि राशन कार्ड में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया अब बेहद सरल हो गई है। केंद्र में तैनात कर्मचारी आवेदन प्रक्रिया से लेकर दस्तावेज प्राप्ति तक ग्रामीणों का पूरा सहयोग करते हैं, जिससे अनपढ़ और भोले-भाले ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती।

छग में कच्चे छप्पर से पक्के आशियाने तक का सफर...



प्रधानमंत्री आवास योजना ने बदली जिंदगी

रायपुर/ संवाददाता

बरसात की हर रात अनिता और उनके परिवार मन में भय लेकर आती थी। टपकती छत, मिट्टी की कमजोर दीवारों और हर मौसम में उजड़ने का भय, यही उनकी जिंदगी की सच्चाई थी। लेकिन अब वही अनिता अपने पक्के घर की चौखट पर खड़ी होकर सुकून और आत्मविश्वास के साथ भविष्य के सपने देख रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनके जीवन की तस्वीर ही बदल दी है। जिला मुख्यालय दंतवाड़ा से करीब 22 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत कमालूर, एक आदिवासी बाहुल्य गांव है। यहां ज्यादातर परिवार खेतों और मजदूरी पर निर्भर हैं। इसी गांव की 28 वर्षीय अनिता पेड़ों को कम उम्र में ही जिंदगी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया था। माता-पिता के निधन के बाद दो छोटे भाइयों और दो बहनों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। परिवार चलाने के लिए उन्होंने खेतों में काम किया, मजदूरी की और हर मुश्किल परिस्थिति से संपर्क करती

रहीं। आर्थिक तंगी इतनी थी कि दो वक्क की रोटी जुटाना भी चुनौती था। ऐसे हालात में पक्का मकान कभी न पूरा होने वाले सपने जैसा था। परिवार एक कच्चे छप्पर वाले घर में रहता था, बरसात आने से पहले छप्पर की मरम्मत कराना जरूरी होता था, लेकिन सीमित आय के कारण यह भी संभव नहीं हो पाता था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका चयन हुआ और शासन द्वारा 1 लाख 20 हजार रुपये की सहायता राशि रवीकृत की गई। इस राशि से उनका पक्का मकान तैयार हुआ, जिसने उनके परिवार को नया जीवन दे दिया। आज अनिता अपने भाई-बहनों के साथ सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में रह रही हैं। वे कहती हैं कि अब पक्के घर में रहने से परिवार को सुरक्षा और सुकून मिला है। उनके चेहरे की मुस्कान इस बात की गवाही देती है कि एक घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, बल्कि वह उम्मीद, सम्मान और आत्मविश्वास का आधार भी होता है। अनिता का मानना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना उनके जैसे गरीब परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह बदलाव ग्रामीण जीवन में आए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों की भी तस्वीर पेश करता है।

जनसमस्या निवारण शिविर में गोरेलाल बरेठ को तत्काल मिली किसान किताब

भड़ैसर शिविर में त्वरित समाधान से खेती-किसानी के कार्य हुए आसान

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार आयोजित सुशासन तिहार 2026 आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है। जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविरों में प्राप्त आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर लोगों को तत्काल राहत प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में जांगीर-चांपा



जिले के जनपद पंचायत नवागढ़ अंतर्गत ग्राम भड़ैसर में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में ग्राम भड़ैसर निवासी श्री गोरेलाल बरेठ अपनी समस्या लेकर पहुंचे। उन्होंने किसान किताब नहीं लेने की जानकारी देते हुए आवेदन प्रस्तुत किया। श्री बरेठ ने बताया कि किसान किताब के अभाव में उन्हें कृषि ऋण, खाद-बीज वितरण तथा किसानों के लिए संचालित विभिन्न शासकीय

योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। आवेदन प्राप्त होते ही संबंधित विभाग के अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की और उन्हें मौके पर ही किसान किताब प्रदान कर दी। किसान किताब मिलने पर श्री गोरेलाल बरेठ ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब उन्हें खेती-किसानी के कार्यों में सुविधा होगी और शासन की योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सुशासन तिहार आम लोगों की समस्याओं के समाधान का एक सार्थक और जनहितकारी अभियान साबित हो रहा है।

कृषि विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय खरपतवार प्रबंधन अनुसंधान परियोजना की तीन दिवसीय वार्षिक बैठक का शुभारंभ

रासायनिक खरपतवारनाशकों का नियंत्रित और प्रभावी उपयोग किया जाए

रायपुर/ संवाददाता

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज यहां अखिल भारतीय समन्वित खरपतवार प्रबंधन अनुसंधान परियोजना की 33वीं वार्षिक समीक्षा बैठक की शुरुआत हुई। इस तीन दिवसीय बैठक का उद्घाटन मुख्य अतिथि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के उप महानिदेशक डॉ. ए. के. नायक द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय जैविक तथा प्रबंधन संस्थान, (आईसीएआर) बरौंडा रायपुर के निदेशक डॉ. पी. के. राय तथा डॉ. राकेश कुमार सहायक महानिदेशक आईसीएआर नई दिल्ली मौजूद थे। यह परियोजना देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में फसलों में खरपतवार नियंत्रण पर अनुसंधान तथा नवीनतम तकनीकों के विकास एवं उनके किसानों के बीच प्रसार हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा जबलपुर

स्थित खरपतवार अनुसंधान निदेशालय के माध्यम से चलाई जा रही है। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉ. ए. के. नायक ने वैज्ञानिकों से खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण के बजाय समन्वित खरपतवार नियंत्रण को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि रासायनिक खरपतवारनाशकों के हानिकारक प्रभावी को देखते हुए उन पर आधारित अनुसंधान को हतोत्साहित किया जाए। डॉ. नायक ने प्राकृतिक एवं जैविक कृषि अपनाने पर जोर देते हुए विभिन्न लाभकारी सूक्ष्मजीवों, केंचुओं तथा कोट पतंगों पर खरपतवारनाशकों के दुष्प्रभाव का अध्ययन करने की सलाह दी। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा कि रासायनिक खरपतवारनाशी यद्यपि खेतों में खरपतवारों के नियंत्रण करने में समर्थ है लेकिन ये पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक है अतः इनका नियंत्रित और प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए। खरपतवार नाशकों का अंधाधुंध उपयोग मानवों और जीव-जंतुओं के स्वास्थ्य तथा



पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि खरपतवारों के प्रबंधन के लिए केवल रसायनों पर निर्भर न रहकर यांत्रिक एवं बायोलॉजिकल नियंत्रण विधियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। समारोह को डॉ. पी. के. राय तथा डॉ. राकेश कुमार ने भी संबोधित किया। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, जबलपुर के प्रभारी डॉ. विजय कुमार चौधरी, प्रमुख वैज्ञानिक ने अखिल भारतीय समन्वित खरपतवार प्रबंधन अनुसंधान परियोजना के तहत देशभर के

सभी 17 केंद्रों में संचालित गतिविधियों एवं उपलब्धियों की जानकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर परियोजना के वार्षिक प्रतिवेदन 2025-26 के साथ ही अन्य प्रकाशनों का विमोचन भी किया गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉ. एस.एस. कोल्हे को खरपतवार प्रबंधन अनुसंधान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान हेतु लाइफटाइम अचिवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना को

खरपतवार प्रबंधन हेतु आईसीएआर बरेठ सेंटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संचालक अनुसंधान एवं बैठक के आयोजन सचिव डॉ. वी.के. त्रिपाठी ने रायपुर केंद्र में इस परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों एवं गतिविधियों की जानकारी दी। परियोजना के प्रमुख अन्वेषक डॉ. श्रीकांत चितले ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि इस समीक्षा बैठक में भारत भर के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में संचालित 17 प्रमुख केंद्रों, तथा 7 स्वयंसेवी केंद्रों में खरपतवार अनुसंधान में कार्यरत वैज्ञानिकों के अलावा अन्य कृषि विश्वविद्यालयों (प्रभू), झुंझर संस्थानों तथा हर्बिसाइड उद्योगों के लगभग 100 वैज्ञानिक शामिल हुए हैं। समीक्षा बैठक के दौरान वर्ष 2025-26 में किए गए अनुसंधान कार्यों एवं विस्तार गतिविधियों की प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी तथा आगामी दो वर्षों के लिए तकनीकी कार्यक्रम पर गहन विचार विमर्श करते हुए इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

संपादकीय

कम्युनिस्टों की दुर्गति पर प्रकाश करात से जुड़ी एक घटना मुझे याद आ रही है। मनमोहन सिंह के कार्यालय के दौरान नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बाबुराम भट्टराई भारत आए थे। प्रसिद्ध समाजवादी नेता शरद यादव ने भट्टराई के स्वागत में एक समारोह आयोजित किया था। समारोह में कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट सहित अन्य दलों के नेता भी आमंत्रित थे। अपनी बारी आने पर प्रकाश करात ने भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और कहा कि नेपाल को भारत कभी बढ़ने नहीं देना चाहता है, दबाकर

कर रखना चाहता है। प्रकाश करात की ऐसी बात सुनकर और बिना विरोध किए ही मोतीलाल बोरा, सुषमा स्वराज आदि चले गए। फिर बाबुराम भट्टराई ने अपने संबोधन में प्रशंसा कर भारत को बड़ा भाई बताया था और मिलकर विकास करने पर प्रतिबद्धता जताई थी। प्रकाश करात की इस बात पर खुद बाबुराम भट्टराई, सुषमा स्वराज, शरद यादव आश्चर्यचकित थे। उपस्थित जनता की प्रतिक्रिया थी कि कम्युनिस्ट देश हित के पक्ष में कभी भी खड़ा नहीं हो सकते हैं। कम्युनिस्टों के राज्यसत्ता से मुक्त होने के पीछे

ऐसा ही कारण रहा है। यह पहली बार हुआ है जब देश के किसी राज्य में कम्युनिस्टों की सरकार नहीं होगी। 1957 के बाद केरल, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में से किसी न किसी राज्य में कम्युनिस्टों की सरकार जरूर रही थी। कभी केरल, तो कभी त्रिपुरा, तो कभी पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों की जीत होती रहती थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों को पैदल कर कम्युनिस्टों की सरकार का संहरा किया था, त्रिपुरा में बीजेपी ने कम्युनिस्टों की सरकार का संहरा किया था

सत्ता मुक्त हो गए कम्युनिस्ट

और अब केरल में कांग्रेस ने कम्युनिस्टों की सरकार का संहरा कर दिया। कम्युनिस्टों की केरल में पिछले दस साल से सरकार चल रही थी? केरल में कम्युनिस्टों की हार क्यों हुई, कांग्रेस की जीत क्यों हुई, इसके पीछे जनता का गणित क्या है? जनता का गणित स्पष्ट था, कम्युनिस्टों की सरकार को दफन करना, केरल की जनता के पास विकल्प का अभाव था, बीजेपी मजबूत नहीं थी, बीजेपी के पास सत्ता बनाने लायक समर्थन शक्ति नहीं थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ ही विकल्प था। राष्ट्रीय

स्तर पर कम्युनिस्टों की वर्तमान ने कोई पहचान नहीं है और न ही जनता की उल्लेखनीय शक्ति उनके पास है, वे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की बी टीम के तौर पर ही सक्रिय हैं, कभी वे कांग्रेस और राहुल गांधी के पक्ष में शतरंज खेलते नजर आते हैं तो कभी वे मुस्लिम समर्थक जिहदी ध्ये पर चलते रहते हैं, हिंदुओं का विरोध करना, राष्ट्रहित के खिलाफ बोलना और भारतीय संस्कृति का संहरा करने की मानसिकता से ग्रसित रहते हैं। माओ, मार्क्स, लेनिन और स्टालिन को छोड़कर इनका कोई भारतीय

महापुरुष आईकॉन नहीं है। वामपंथ एक विदेशी विचार है, यह अवधारणा आम भारतीय के अंदर बैठ गयी है, इस कारण आम भारतीय के अंदर वामपंथ प्रेरक बन नहीं सकता है, स्वीकार नहीं हो सकता है। यही कारण है कि केन्द्रीय सत्ता के लायक वामपंथ को कभी स्वीकार नहीं किया गया। कम्युनिस्टों को विकास विरोधी कहना सही होगा क्या? कम्युनिस्टों को स्थिरता विरोधी कहना सही होगा क्या? कम्युनिस्टों को शांति विरोधी कहना सही होगा।

विकास में भेदभाव का शिकार हो रहे हैं प्रमुख तीर्थस्थल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के कारण काशी में जहां तरक्की और घोषणाओं की बरसात हो रही है, वहीं देश के दूसरे प्रमुख हिन्दू तीर्थ स्थल विकास की बाट जोह रहे हैं। मोदी का निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा जोर काशी तक सीमित कर रहा गया है। यदि यह मान भी लिया जाए कि काशी हिन्दुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है, इसलिए इसके विकास की दरकार है, तो ऐसे में देश के प्रमुख राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अन्य तीर्थ स्थल विकास की दौड़ में काशी से काफी पीछे क्यों हैं। कारण साफ नजर आता है कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र होने के कारण काशी में विकास की गंगा बह रही, वहीं अन्य प्रमुख धार्मिक स्थल वाले जिले बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं।

(सोमेश्वर योगी)

काशी के अलावा देश के अन्य प्रमुख तीर्थ स्थल वाले जिलों में विकास चोटी की रफ्तार से रेंग रहा है या फिर उसकी सुध नहीं ली जा रही है। काशी के अलावा देश के प्रमुख हिन्दू तीर्थ स्थलों में आधारभूत सुविधाओं की बेहद कमी है। वैष्णो देवी के लिए प्रसिद्ध कटरा जिले में मूसलाधार बारिश के दौरान भूस्खलन की गंभीर समस्या है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के कारण काशी में जहां तरक्की और घोषणाओं की बरसात हो रही है, वहीं देश के दूसरे प्रमुख हिन्दू तीर्थ स्थल विकास की बाट जोह रहे हैं। मोदी का निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा जोर काशी तक सीमित कर रहा गया है। यदि यह मान भी लिया जाए कि काशी हिन्दुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है, इसलिए इसके विकास की दरकार है, तो ऐसे में देश के प्रमुख राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अन्य तीर्थ स्थल विकास की दौड़ में काशी से काफी पीछे क्यों हैं। कारण साफ नजर आता है कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र होने के कारण काशी में विकास की गंगा बह रही, वहीं अन्य प्रमुख धार्मिक स्थल वाले जिले बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं।

वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में विकास के तहत कुल 48,459 करोड़ रुपये की लागत से 580 परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया है। काशी के विकास की घोषणाओं की शुरुआत मोदी के पहली बार सांसद बनने के साथ ही शुरू हो गई थी। यह मिलसिला लगातार जारी है। छल ही में पीएम मोदी ने अपने दो दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान 6332 करोड़ रुपये की कुल 163 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें गंगा पर सिनेचर ब्रिज सबसे बड़ी परियोजना है। जिसकी लागत करीब 2464.46 करोड़ है। यह ब्रिज काशी की कनेक्टिविटी और ट्रैफिक व्यवस्था को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री के हथौड़े 1054.69 करोड़ की 50 परियोजनाओं का लोकार्पण और 5277.39 करोड़ की 113 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया।

काशी के अलावा देश के अन्य प्रमुख तीर्थ स्थल वाले जिलों में विकास चोटी की रफ्तार से रेंग रहा है या फिर उसकी सुध नहीं ली जा रही है। काशी के अलावा देश के प्रमुख हिन्दू तीर्थ स्थलों में आधारभूत सुविधाओं की बेहद कमी है। वैष्णो देवी के लिए प्रसिद्ध कटरा जिले में मूसलाधार बारिश के दौरान भूस्खलन की गंभीर समस्या है। जम्मू और कटरा के बीच सड़क और रेल संपर्क अक्सर टूट जाता है। विशेष रूप से, 2025 की बाढ़ के बाद से ट्रेनों का रफ्तार और पूर्ण (जैसे कटुआ, उधमपुर के पास) को नुकसान ने यात्रा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका दिया है। कटरा में स्मार्ट सड़कों, सूक्ष्मव्यक्ति पार्किंग, और आधुनिक बुनियादी ढांचे की कमी है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए मौजूदा सुविधाएं नाकाम हैं। बढ़ती भीड़ के कारण गांवियों में पैयजल और निरंतर बिजली आपूर्ति की समस्या बनी रहती है। लगातार निर्माण, वनों को काटने और भीड़भाड़ के कारण पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

राम मंदिर के विस्तार अयोध्या में बाल विकास विभाग की एक रिपोर्ट ने जिले में कुपोषण की चिंताजनक स्थिति को उजागर भी है। जिले के 2,381 आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 2,28,018 बच्चों की जांच में 7,520 बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। इनमें 1,199 बच्चे अति कुपोषित (सैम) और 6,321 बच्चे मध्यम गंभीर कुपोषित (मैम) श्रेणी में हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में

264 और 2024-25 में 286 अति कुपोषित बच्चों को पुनर्वास केंद्र भेजा गया। विकास परियोजनाओं के कारण हजारों लोग, विशेषकर छोटे व्यापारी और गरीब, अपने पुरतैनी आवासों और व्यवसायों से विस्थापित हो गए हैं। परियोजनाओं के कारण उड़ने वाली धूल और निर्माण सामग्री से स्थानीय लोगों को सांस संबंधी बीमारियां हो रही हैं। जल प्रदूषण और सीवर के गंदे पानी के धरों में घुसने की समस्या से लोग लंबे समय से परेशान हैं। पुरानी अयोध्या (फेजाबाद) और अयोध्या धाम के बीच अवागमन में मुश्किल हो रही है।

देश के 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल केदारनाथ के रुद्रप्रयाग जिले के कई सुदूरवर्ती गांव अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव से जूझ रहे हैं, जहां आपदा प्रभावित क्षेत्रों में संपर्क मार्ग

भीड़ प्रबंधन अब भी मुख्यतः पुलिस के भारों से संचालित हो रहा है। कई बार मास्टर प्लान और विस्तृत प्रस्ताव तैयार किए गए, लेकिन जमीन पर उतरते हुए नजर नहीं आया। हिन्दुओं के प्रमुख तीर्थस्थल में शुभार प्रयागराज शहर वर्तमान में कई गंभीर सामाजिक और बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। मुख्य समस्याओं में गंगा-यमुना की बाढ़ से फसल व जनजीवन का नुकसान, बजाजवाती नालियां व कूड़े के ढेर के कारण गंदगी, सीवर लाइन का अभाव, यातायात जाम और अवैध अतिक्रमण शामिल हैं। इसके अलावा, बाढ़ के बाद बीमारियां और मच्छरों का प्रकोप भी एक बड़ी चुनौती है। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में विकास और पर्यटन के बावजूद कई प्रमुख सामाजिक और नागरिक समस्याएं मौजूद हैं, जो स्थानीय निवासियों और



बाधित होने और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को स्वास्थ्य उपचार के लिए भटकना पड़ता है। भारी बारिश के कारण संपर्क मार्ग बाधित होना भी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच में एक बड़ी बाधा है। जिले भर में लगभग 25 जल स्रोत सूख चुके हैं, जिससे पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। पानी की कमी से नाराज लोग जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। इसी तरह उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, धार्मिक पर्यटन के दबाव और प्रशासनिक चुनौतियां मौजूद हैं। नालों और सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण के कारण जल निकासी बाधित हो रही है। मानसून से पहले नालों पर अतिक्रमण के कारण जलप्रवाह का खतरा बना रहता है। इतकी पैड़ी और आसपास के क्षेत्रों में भिखारूत एक बड़ी समस्या है। चारधाम यात्रा के सुचारु न रहने या व्यवस्थाओं के कारण स्थानीय होटलों और पर्यटन व्यवसाय पर भी असर पड़ रहा है।

कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में 30,000 करोड़ से अधिक की ब्रज मास्टर प्लान परियोजनाओं और नई आवासीय योजनाओं के लिए 850 करोड़ के बावजूद, कई विकास कार्य फाटलों में अटक रहे हैं। वर्ष 2026-2030 के मास्टर प्लान के अंतर्गत शहर को छह-सौड़ कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने का विज़न है, लेकिन प्रशासनिक प्रक्रियाओं के चलते जमीनी स्तर पर गति धीमी है। मथुरा-वृंदावन में वर्षभर धार्मिक आयोजनों की लंबी श्रृंखला चलती रहती है। प्रमुख आयोजनों में होलिकोत्सव, मुद्दिआ मेला, चण्डीमाष्टी, राधाष्टमी, छुलन उत्सव, कार्तिक मास, गोवर्धन पूजा और ब्रज की विभिन्न परिक्रमाएं शामिल हैं। आयोजनों के दौरान ब्रह्मलुओं की संख्या 8 से 10 लाख तक पहुंच जाती है।

तीर्थयात्रियों को प्रभावित करती है। गुजरात सोमनाथ मंदिर (प्रथम ज्योतिर्लिंग) जिले में पर्यटन और आस्था के केंद्र होने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण सामाजिक और नागरिक समस्याएं भी विद्यमान हैं। इस क्षेत्र में दलित समुदाय के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं (जैसे रत्ना की घटना) और हाशिए पर स्थित समुदायों के उपपीड़न में समस्या रही है। जमीन के अधिकारों को लेकर विवाद और अवैध सरंचनाओं को हटाने के दौरान लोगों का विस्थापन और पुनर्वास न होना एक प्रमुख समस्या है। वैश्वकल जैसे तटीय क्षेत्रों में बंदरगाह आधारित विकास के बावजूद नागरिक सुविधाओं की कमी है। सोमनाथ मंदिर के कारण बड़ी संख्या में पर्यटकों के आगमन से स्थानीय बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ता है, जिससे स्वच्छता और यातायात प्रबंधन और सार्वजनिक सुविधाओं में कमी रहती है। तटीय जिला होने के कारण यहां चक्रवात और बाढ़ का खतरा बना रहता है, जिसके लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को लगातार काम करना पड़ता है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं और उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे का अभाव है। तमिलनाडु के रामेश्वरम (रामनाथस्वामी मंदिर) रामनाथपुरम जिला धार्मिक और तटीय पर्यटन के बड़े अतिक्रमण के बावजूद अग्रणी बुनियादी ढांचा (जैसे- बेहतर सड़कें, आवास और सार्वजनिक सुविधाएं) मांग के अनुरूप तालमेल विधान में संघर्ष कर रहा है। रामेश्वरम और धनुष्कोडी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक भारी आवागमन के कारण सड़कों पर दबाव, जिससे अक्सर यातायात जाम की स्थिति बनती है। पीक सीजन में आवास, पार्किंग और स्वच्छता सुविधाओं की कमी, जो पर्यटकों के अनुभव को प्रभावित करती है।

एआई चमत्कारी भी है और विनाशकारी भी, इसके प्रभावों को लेकर दुनियाभर की सरकारों की नींद उड़ गई है

(नीरज कुमार दुबे)

एआई के क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास के बीच एक नया मॉडल वैश्विक चिंता का केंद्र बन गया है। यह है एन्थ्रोपिक द्वारा विकसित मॉडल मिथोस। यह उन्नत प्रणाली जहां साइबर सुरक्षा के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, वहीं इसके संभावित दुरुपयोग को लेकर सरकारों, बैंकों और विशेषज्ञों के बीच गंभीर आशंकाएं भी उभर रही हैं। हम आपको बता दें कि मिथोस एक ऐसा एआई मॉडल है जो कंप्यूटर प्रणालियों में मौजूद छिपी कमजोरियों को पहचानने और उनका फायदा उठाने में सक्षम बताया गया है। कंपनी के अनुसार यह उन न्युट्रियों को भी खोज सकता है जिनके बारे में सॉफ्टवेयर बनाने वालों को खुद जानकारी नहीं होती। इन्हें जीरो डे कमजोरियां कहा जाता है, क्योंकि इनके सामने आने के बाद सुधार का समय नहीं मिल पाता।

ब्रिटेन के एआई सुरक्षा संस्थान ने भी मिथोस का परीक्षण किया है और इसे पहले के मॉडलों की तुलना में अधिक सक्षम और खतरनाक बताया है। यह मॉडल कई चरणों वाले साइबर हमलों का अनुकरण करने में सफल रहा है और बिना मानवीय निर्देश के कमजोरियों को पहचान कर सकता है। एआई के क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास के बीच एक नया मॉडल वैश्विक चिंता का केंद्र बन गया है। यह है एन्थ्रोपिक द्वारा विकसित मॉडल मिथोस। यह उन्नत प्रणाली जहां साइबर सुरक्षा के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, वहीं इसके संभावित दुरुपयोग को लेकर सरकारों, बैंकों और विशेषज्ञों के बीच गंभीर आशंकाएं भी उभर रही हैं। हम आपको बता दें कि मिथोस एक ऐसा एआई मॉडल है जो कंप्यूटर प्रणालियों में मौजूद छिपी कमजोरियों को पहचानने और उनका फायदा उठाने में सक्षम बताया गया है। कंपनी के अनुसार यह उन न्युट्रियों को भी खोज सकता है जिनके बारे में सॉफ्टवेयर बनाने वालों को खुद जानकारी नहीं होती। इन्हें जीरो डे कमजोरियां कहा जाता है, क्योंकि इनके सामने आने के बाद सुधार का समय नहीं मिल पाता। मिथोस की यही क्षमता इसे अत्यंत शक्तिशाली और साथ ही खतरनाक बनाती है। कंपनी ने सात अप्रैल को इस मॉडल के अस्तित्व की घोषणा की थी, लेकिन इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए जारी करने से साफ इंकार कर दिया। कारण स्पष्ट है कि यदि यह तकनीक गलत हाथों में चली गई तो वैश्विक साइबर सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। हालांकि, सीमित रूप से कुछ कंपनियों और बैंकों को इसके परीक्षण की अनुमति दी गई है ताकि वह इसके जोखिमों को समझ सकें। हाल ही में स्थिति तब और गंभीर हो गई जब यह

सामने आया कि कुछ अनाधिकृत लोगों ने इस मॉडल तक पहुंच हासिल कर ली थी। यह घटना इस बात का संकेत है कि इतने संवेदनशील उपकरण को पूरी तरह निर्यात रखा किटना कठिन है। इससे तकनीकी कंपनियों की क्षमता पर भी सवाल उठे हैं कि वह अपने सबसे जोखिमपूर्ण उत्पादों को कितनी सुरक्षित रख सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मिथोस केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि एआई की तेजी से बढ़ती शक्ति का यह अत्यधिक सुरक्षित प्रणालियों पर किटना प्रभाव है। यह विशेषज्ञों का मानना है कि इस मॉडल को लेकर जितनी चर्चा हो रही है, उसमें कुछ हद तक अतिशयोक्ति भी शामिल हो सकती है। उनका कहना है कि कई सस्ते मॉडल भी कुछ कमजोरियों की पहचान करने में सक्षम हैं। इसके अलावा अधिकतर साइबर हमले अब भी साधारण कमजोरियों जैसे कमजोर पासवर्ड या पुराने सॉफ्टवेयर के कारण होते हैं।



गई है और इसके विस्तार को लेकर भी सावधानी बरती जा रही है। भारत में भी इस मुद्दे ने तेजी से ध्यान आकर्षित किया है। देश को इस मॉडल के शुरुआती परीक्षण से बाहर रखा गया, जिससे नीति निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञों के बीच चिंता बढ़ गई। सरकार अब अमेरिका और कंपनी के साथ बातचीत कर रही है ताकि भारतीय कंपनियों को भी इस तकनीक तक उचित पहुंच मिल सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विषय को अत्यंत गंभीर बताया है। यह है कि यह साइबर चुनौती बहुत बड़ी हो सकती है। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बैंकों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकों की हैं। उद्देश्य यह है कि देश के महत्वपूर्ण ढांचे जैसे बैंकिंग नेटवर्क, दूरसंचार और बिजली प्रणाली को सुरक्षित रखा जा सके। भारत की चिंता केवल पहुंच तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य के जोखिमों को लेकर भी है। यदि अन्य कंपनियां भी इसी तरह के मॉडल विकसित करती हैं और उनका वितरण असमान रहता है, तो कुछ देशों की सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है। यही कारण है कि भारत समान अवसर और संतुलित नीति की मांग कर रहा है। इसके साथ ही, देश की साइबर सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया गया है। उन्हें संवेदनशील प्रणालियों की जांच करने और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी तकनीक दोषाग्नी तलवार की तरह है, इसका उपयोग सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है और हमलों के लिए भी। बहरहाल, मिथोस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब केवल सुविधा का साधन नहीं रही, बल्कि यह वैश्विक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और नीति निर्माण का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि दुनिया इस नई तकनीकी शक्ति के साथ संतुलन कैसे बनाती है ताकि इसका लाभ भी मिले और जोखिम भी नियंत्रित रहे। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ कार्यक्रम

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर गोबरहीन शिव मंदिर में हुआ भव्य आयोजन

कोण्डगांव। जिले के केशकाल विकासखण्ड अंतर्गत स्थित प्राचीन गोबरहीन शिव मंदिर प्रांगण में सोमवार को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन ब्रह्मा एवं उसाह के साथ किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सोमनाथ मंदिर में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी उपस्थित जनप्रतिनिधि जनसमुदाय द्वारा देखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम उपस्थित रहे। कार्यक्रम को शुरुआत विधायक टेकाम द्वारा गोबरहीन शिव मंदिर में पूजा-अर्चना एवं क्षेत्रवासियों को सुख-समृद्धि की कामना के साथ हुई। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ अभिषेक कार्यक्रम के माध्यम से किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार पूरे जिले में भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर हमारी सांस्कृतिक विरासत और इतिहास को स्मरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गढ़घनोर स्थित गोबरहीन मंदिर छठवीं शताब्दी की अत्यंत प्राचीन धरोहर है, जहां प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर



विशाल मेले का आयोजन होता है। इस आयोजन से मंदिर को नई पहचान और व्यापक ख्याति मिलेगी। विधायक ने बताया कि इस क्षेत्र को संरक्षित करने एवं

पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु कार्ययोजना तैयार कर कार्य किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए विधायक

टेकाम ने कहा कि मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए, लेकिन इसकी आस्था और परंपरा को कभी समाप्त नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह पर्व स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक है। इस आयोजन के माध्यम से पूरे देश को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर नूपुर राशि पत्रा ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि विधायक के मार्गदर्शन में गढ़घनोरा क्षेत्र के संरक्षण एवं सांस्कृतिक धरोहरों को संभालने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही जिले में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए भी योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल जिले को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं

नैनो यूरिया 16 प्रतिशत एवं नैनो डी.ए.पी. 8:16 की उपयोग विधि

काकिरा। नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के उपयोग संबंधी सलाह देते हुए कृषि विभाग के उप संचालक जितेन्द्र कोमरा ने बताया कि नैनो यूरिया इफको द्वारा विकसित नैनो तकनीक पर आधारित तरल उर्वरक है, जो पारंपरिक उर्वरक यूरिया का एक आधुनिक और प्रभावी विकल्प है। यह 500 मिली की बोतल में आता है और नाइट्रोजन को कमी को पूरा करता है। 500 मिली की एक बोतल सामान्य यूरिया के एक पूरे बैग (45-50 किग्रा) के बराबर पोषक तत्व प्रदान करती है, जिससे किसानों को लागत कम होती है और पैदावार बढ़ती है। नैनो यूरिया को मुख्य विशेषताएं और फायदों के संबंध में जानकारी देते हुए उप संचालक ने कृषि ने बताया कि इसमें मौजूद नैनो-कण (20-50 नैनोमीटर) पौधों की पत्तियों के रंधों के माध्यम से आसानी से अवशोषित हो जाते हैं, जिससे नाइट्रोजन उपयोग दक्षता 80 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाती है। यह मिट्टी की सेहत को सुधाराता है और लौहिंग व गैसीय उत्सर्जन को कम करता है। फसल की सक्रिय वृद्धि के दौरान 2-4 मिली नैनो यूरिया प्रति लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर स्प्रे किया जाता है। लागत में कमी 500 मिली की बोतल का मूल्य सामान्य यूरिया के एक बोरे से बहुत कम है, जिससे खेती की लागत घटती है। अति शीघ्र अवधि किस्में (80 से 100 दिन) धान की बोवाई अथवा रोपाई के 30-35 दिनों के पश्चात् प्रथम स्प्रे प्रति एकड़ नैनो यूरिया (16 प्रतिशत) की 500 मिली. मात्रा को 125-150 लीटर पानी में घोलकर खड़ी फसल में पंणीय छिड़काव किया जाना चाहिए। तथा द्वितीय स्प्रे धान की बोवाई अथवा रोपाई के 55-60 दिनों पश्चात् प्रति एकड़ नैनो यूरिया (16 प्रतिशत) की 500 मिली. मात्रा को 125-150 लीटर पानी में घोलकर खड़ी फसल में पंणीय छिड़काव किया जाए।

मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान से लोगों को मिल रहा स्वास्थ्य लाभ

कोण्डगांव। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर 13 अप्रैल से प्रारंभ किए गए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान के माध्यम से बस्तर संभाग के सभी जिलों के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमों घर-घर पहुंचकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं तथा गंधीर एवं संक्रामक बीमारियों की समय पर पहचान कर उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर नूपुर राशि पत्रा के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.के. चतुर्वेदी के नेतृत्व में जिले में अभियान का सफल संचालन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा गांव-गांव जाकर सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण के साथ कुष्ठ रोग, टीबी, कुपोषण एवं अन्य बीमारियों की भी जांच की जा रही है। अभियान के दौरान जिले के एक ग्रामीण परिवार में स्वास्थ्य परीक्षण के समय कुष्ठ रोग के लक्षण पाए गए। स्वास्थ्य टीम द्वारा विस्तृत जांच किए जाने पर रोग की पुष्टि हुई। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों की भी जांच की गई, जिसमें संक्रमण के अन्य मामले भी सामने आए। चिकित्सकों के अनुसार लंबे समय तक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहने से परिवार के अन्य सदस्यों में

घर-घर पहुंच रही स्वास्थ्य सेवाएं



भी संक्रमण फैलने की संभावना बनी रहती है। समय पर पहचान होने से दोनों मरीजों का उपचार तत्काल प्रारंभ कर दिया गया तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा नियमित रूप से दवा सेवन भी सुनिश्चित कराया जा रहा है।

गोलापल्ली-किस्टाराम परिक्षेत्र में फॉरेस्ट नाका व जंगलों के रास्तों से खुलेआम तेंदूपत्ता परिवहन

कोटा। कोटा उप वनमंडल के गोलापल्ली, किस्टाराम परिक्षेत्र में तेलंगाना के ठेकेदारों द्वारा कथित रूप से अवैध तरीके से कच्चा तेंदूपत्ता खरीदी कर फॉरेस्ट नाकों व जंगलों के रास्तों से खुलेआम परिवहन किए जाने की चर्चा क्षेत्र में तेज हो गई है। तेलंगाना के सीमावर्ती गांवों में फड़ लगाकर तेंदूपत्ता की गड़ियां बिछाई जा रही हैं और बड़े पैमाने पर खरीदी का काम चल रहा है। सूत्रों के अनुसार एक ही ठेकेदार द्वारा 14 से 15 स्थानों पर फड़ संचालित किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक दोनों परिक्षेत्रों से करोड़ों रुपये मूल्य का तेंदूपत्ता परिवहन हो चुका है, लेकिन विभागीय स्तर पर किसी प्रकार की टोस कार्रवाई नजर नहीं आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदारों ने खरीदी दर और भुगतान व्यवस्था को लेकर गांवों में खुली चर्चा नहीं की है। अलग-अलग क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों को सुपरवाइजर नियुक्त कर उनकी माध्यम से तेंदूपत्ता खरीदी कराया जा रहा है तथा प्रत्येक गड़ियां पर कमीशन दिया जा रहा है। जब आदिवासी जनप्रतिनिधि ही पेशा कानून क्षेत्र में ग्राम सभा जैसे महत्वपूर्ण नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो भविष्य में ग्रामीणों द्वारा किसी भी कार्य को नियमपूर्वक और पारदर्शिता के साथ कैसे किया जा सकेगा।



सरकारी समर्थन मूल्य 5.55 रुपये प्रति गड़ियां निर्धारित है

जानकारी के अनुसार तेंदूपत्ता का सरकारी समर्थन मूल्य 5.55 रुपये प्रति गड़ियां निर्धारित है। एक गड़ियां में 52 पत्ते होते हैं तथा प्रत्येक पत्ते की दर 11 पैसे तय की गई है। इसके बावजूद क्षेत्र में संगठनकर्ताओं से 3 से 4 रुपये प्रति गड़ियां की दर से तेंदूपत्ता खरीदे जाने की बात सामने आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गोलापल्ली और किस्टाराम क्षेत्र में उत्तम गुणवत्ता वाले तेंदूपत्ते का संग्रहण होता है, लेकिन गुणवत्ता के अनुरूप संगठनकर्ताओं को उचित दर नहीं मिल पा रही है।

घरेलू लकड़ी पर कार्रवाई, लेकिन तेंदूपत्ता परिवहन पर चुप्पी

इधर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले घरेलू उपयोग के लिए लॉर्ड गई सागौन लकड़ी पर विभाग तत्काल कार्रवाई करता था, लेकिन अब प्रसिद्धि लाने और रुपये मूल्य के कथित उद्वेग तेंदूपत्ता परिवहन के बावजूद विभागीय सक्रियता दिखाई नहीं दे रही है।

फायदामुझा चेकपोस्ट के बावजूद जारी परिवहन से उठे सवाल

गोलापल्ली और किस्टाराम परिक्षेत्र के लिए तेलंगाना सीमावर्ती गंव फायदामुझा दिशा 212 बटोरिथिन कैम्प के पास चेकपोस्ट बनाया गया है, जहां जांच के लिए तीन लकड़वालों की इट्टी लम्बाई गई है। इसके बावजूद कच्चा तेंदूपत्ता परिवहन लगातार जारी रहने से विभाग की कार्यक्षमता पर सवाल उठे हो रहे हैं।

एएमएनएस इंडिया किरंदुल द्वारा ग्राम पंचायत हिरोली में स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन

ग्रामीणों को मिल्नी मुफ्त इलाज और दवाइयों की सौगात

दत्तेवाड़ा। आर्सेल मितल निर्माण स्टील इंडिया किरंदुल ने जन सेवा की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ग्राम पंचायत हिरोली में एक बड़े स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया ताकि गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों को उनके घर के पास ही बेहतर इलाज मिल सके। इस शिविर की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटने लगे और कुल 85 लोगों ने अपनी सेहत की जांच करवाई। शिविर में आए डॉक्टरों ने 59 मरीजों की बारीकी से जांच की और बीमारों के इलाज से उन्हें भौके पर ही मुफ्त में दवाइयां बांटीं जिससे ग्रामीणों को शहर जाकर महंगी दवा खरीदने की चिंता से मुक्ति मिली। शरीर के भीतर की बीमारियों को जानने के लिए शिविर में खून की जांच की सुविधा भी रखी गई थी जिसमें 26 लोगों के खून की जांच कर उनके ब्लड प्रेशर, शुगर और मलेरिया की स्थिति का पता लगाया गया। इस नेक



काम को पूरा करने में गांव के सरपंच, स्वास्थ्य केंद्र की सीएचओ और गांव-गांव जाकर सेवा देने वाली पितामिन बहनो ने अपना पूरा सहयोग दिया। एएमएनएस इंडिया की टीम और गांव के इन जागरूक प्रतिनिधियों ने साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया कि शिविर में आने वाले हर एक व्यक्ति को सही सलाह और उपचार मिल सके। हिरोली के लोगों ने कंपनी के

एनएमडीसी परियोजना चिकित्सालय को स्मार्ट हॉस्पिटल ऑफ द ईयर सम्मान



किरंदुल। एनएमडीसी बीआईओएम किरंदुल कॉम्प्लेक्स स्थित परियोजना चिकित्सालय को Integrated Health and Wellbeing Council द्वारा Novotel Hyderabad Convention Centre में आयोजित भव्य समारोह में स्मार्ट हॉस्पिटल ऑफ द ईयर पुरस्कार (टिपर-2/3 शहर श्रेणी) से सम्मानित किया गया। यह गौरवपूर्ण पुरस्कार परियोजना की ओर से डॉ. एम वी लाल एवं डॉ. अभिषेक ने ग्रहण किया। यह प्रतिष्ठित सम्मान परियोजना चिकित्सालय द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, आधुनिक तकनीकी सुविधाओं,

डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली एवं जनसेवा के प्रति समर्पण का प्रमाण है। आज परियोजना चिकित्सालय अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा युगवत्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से कर्मचारियों, उनके आश्रितों एवं आसपास के ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को निरंतर बेहतर उपचार उपलब्ध करा रहा है। अतिमत्तम मुर्खजी अध्यक्ष सहस्रबंध निदेशिका की दृष्टि से सोच एवं डिजिटलीकरण को पहल से परियोजना चिकित्सालय ने आधुनिक एवं स्मार्ट स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित की है। अस्पताल

में आईसीयू, एनआईसीयू, सीटी-स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, फेको सर्जरी, ब्लाड बैंक, कर्पोरेंट लेब, आपातकालीन सेवाएं सहित अनेक विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो इसे क्षेत्र के अग्रणी चिकित्सालयों में शामिल करती हैं। किरंदुल कॉम्प्लेक्स के रविंद्र नारायण, अधिशासी निदेशक के कुशल नेतृत्व एवं श्रीमती के. एल. नागवैणी, उपमहास्रबंधक (मानव संसाधन) के मार्गदर्शन में चिकित्सालय के डॉक्टरों, नर्सों एवं पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी मेहनत, सेवा भावना एवं समर्पण से यह उपलब्धि हासिल की है।

एनएमडीसी के स्विमिंग पूल में आम नागरिकों के प्रवेश पर रोक को लेकर नगरपालिका उपाध्यक्ष ने जताया विरोध



किरंदुल। नगरपालिका परिषद किरंदुल के उपाध्यक्ष बबलू सिद्धीकी ने एनएमडीसी प्रबंधन को पत्र लिखकर स्विमिंग पूल में आम नागरिकों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध का कड़ा विरोध किया है। जारी पत्र में कहा गया है कि एनएमडीसी द्वारा संचालित स्विमिंग पूल में केवल एनएमडीसी कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को ही प्रवेश देने का निर्णय लिया गया है, जिससे नगर के सामान्य नागरिक स्वयं को उर्षित महसूस कर रहे हैं। पत्र में उल्लेख किया गया कि किरंदुल केवल एनएमडीसी कर्मचारियों का नगर नहीं, बल्कि हजारों स्थानीय नागरिकों का भी शहर है, जिनके सहयोग, संसाधनों और सामाजिक सहभागिता से ही एनएमडीसी वर्षों से यहां कार्यरत है। ऐसे में सार्वजनिक उपयोग की सुविधा से स्थानीय नागरिकों को वंचित करना उचित नहीं माना जा सकता। नगर पालिका उपाध्यक्ष बबलू सिद्धीकी ने कहा कि स्विमिंग पूल जैसी सार्वजनिक सुविधा को निर्धारित नियम एवं शुल्क के अंतर्गत नगरवासियों के लिए भी खोला जाना चाहिए, ताकि सभी नागरिक इसका लाभ ले सकें एवं साथ ही उन्होंने कहा कि नगर के नागरिकों की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान किया जाना आवश्यक है तथा एनएमडीसी प्रबंधन को इस विषय पर जल्द उचित निर्णय लेना चाहिए।

21 मोतियाबिंद मरीजों का सफल ऑपरेशन

काकिरा। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान के तहत जिले के सुदूर वनांचल और दूरस्थ बसाहटों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच लगातार बढ़ रही है। कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के निर्देशानुसार सभी सौंदर्य मरीजों को उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर कर उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। अब स्वास्थ्य विभाग की टीमों गांव-गांव पहुंचकर लोगों की जांच और उपचार सुनिश्चित कर रही हैं। इस अभियान ने न केवल स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाया है, बल्कि सुदूर अंचल में रहने वाले लोगों के मन में विश्वास की नई किरण भी जगाई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.सी. ठाकूर ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान के कारण अब जिले के सुदूर गांवों के लोगों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय करने को मजबूर नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं उनके द्वार तक पहुंच रही हैं। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक जांच के दौरान 04 लाख 29 हजार 279 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। जांच के दौरान मलेरिया, टीबी, कुष्ठ, मुख कैंसर, सिस्कुल सेल एवं



मोतियाबिंद जैसी गंधीर बीमारियों की पहचान कर समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है, इससे बीमारियों की जटिलताओं को कम करने में मदद मिल रही है। यह भी बताया गया कि अभियान को प्रभावी बनाने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग किया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज एवं सुपर स्पेशियलिटी संस्थानों तक बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है। वहीं मोबाइल मेडिकल यूनिट और स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से दूरस्थ इलाकों तक भी उपचार सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत काकिरा जिले के पोखनलाल 60 वर्ष, जोहतरिन 56 वर्ष, देवचंद 52 वर्ष सहित कुल 21 मोतियाबिंद मरीजों का जिला चिकित्सालय काकिरा में सफल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद मरीजों की आंखों की रोशनी लौटने पर उन्होंने जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया।

क्रेडा विभाग के मैकेनिक द्वारा सोलर झ्यूल पंप का तत्काल मरम्मत

काकिरा। दुर्ग कोदल विकासखण्ड के ग्राम पंचायत डेडकारानहूर में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत क्रेडा द्वारा सोलर झ्यूल पंप स्थापित किया गया है, उक्त संयंत्र के खराब होने की जानकारी मिलने पर क्रेडा विभाग के मैकेनिक द्वारा तत्काल संयंत्र को सुधार कर सुचारू रूप से क्रियाशील कर दिया गया है। इस आशय की जानकारी देते हुए क्रेडा विभाग के सहायक अभियंता ने बताया कि वर्तमान में यह संयंत्र क्रियाशील अवस्था में है तथा ग्रामवासियों को पेयजल प्राप्त हो रहा है।



एनएमडीसी किरंदुल सीएसआर के तहत निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर आयोजित

किरंदुल। किरंदुल एनएमडीसी परियोजना के अधिशासी निदेशक रवीन्द्र नारायण के निर्देशन एवम डीजीएम एचआर के एल नागवैणी के मार्गदर्शन में नैगम सामाजिक दायित्व के तहत परियोजना के आसपास के आदिवासी ग्रामीणों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। इसी तारतम्य में परियोजना द्वारा सीएसआर के तहत निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर लगाकर ग्राम पंचायत कोडैना के ग्रामीणों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया गया। जिसमें निःशुल्क खून जांच, ब्लडप्रेशर, मलेरिया जांच, खांसी, सर्दी एवं जुखार आदि बीमारियों की



जांच की गई। मेडिकल जांच टीम में चिकित्सा अधिकारी डॉ रामकृष्ण ने 55 ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की। इस दौरान मेला नर्स सुनीता, मधुसूदन मंडल, सुनीता बघेल, सुजीता कुंजाम उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

फर्छी जाति प्रमाण पत्र का बड़ा खेल उजागर, बैगा समाज ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौपा ज्ञापन

गौरैया-पेंडू-मरवाही। जिले में फर्छी जाति प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी नौकरियां हासिल करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। विशेष पिछड़ी जनजाति और राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले बैगा समाज के नाम पर फर्छी प्रमाण पत्र बनाए जाने का आरोप लगाते हुए बैगा समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौपा। अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस की राष्ट्रीय समन्वयक अर्चना पौरे और 'नांगा बैगा जनजाति संगठन' के नेतृत्व में समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए गंभीर आरोप लगाए। ज्ञापन में कहा गया है कि बिलासपुर जिले के ग्राम पोड़ी (सोपत) के करीब 55 लोगों ने कूटस्थ दस्तावेजों के जरिए फर्छी तरीके से 'बैगा' जनजाति का प्रमाण पत्र बनवा लिया है। समाज के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि इन फर्छी प्रमाण पत्रों के आधार पर बड़ी संख्या में लोग सरकारी नौकरियों में कार्यरत हैं। इनमें शिक्षक, हाईकोर्ट कर्मचारी, आर्मी, बीएसएफ, कृषि विभाग और स्वास्थ्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां शामिल हैं। बैगा समाज ने आशंका जताई है कि यदि पूरे परिवारों को जांच की जाए तो फर्छी नियुक्तियों की संख्या 150 से 200 तक पहुंच सकती है। मामले में बैगा समाज का कहना है कि सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति के आर्थिक उत्थान के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर बिना परीक्षा सौंपी भर्ती का प्रावधान किया है। लेकिन बाहरी लोग फर्छी दस्तावेज तैयार कर इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, जिससे वास्तविक बैगा युवाओं के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। समाज के लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि जिन व्यक्तियों ने प्रमाण पत्र बनवाए हैं, उनका बैगा समाज से कोई सामाजिक या पारिवारिक संबंध नहीं है। उन्होंने तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों और एसडीएम को भूमिका पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। बैगा समाज ने पूरे मामले को जांच रण्य स्तरीय जाति सत्यापन समिति से कराने और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं कलेक्ट्रेट ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच कराने का आश्वासन दिया है।

बिलासपुर में नहर में मिला वृद्ध का शव, इलाके में फैली सनसनी

बिलासपुर। न्यायधानी बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक वृद्ध का शव नहर में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना खुंटघाट स्थित छोटी नहर की है, जहां स्थानीय लोगों ने शव को पानी में तैरते हुए देखा। जानकारी के अनुसार, सुबह सांघीपारा वार्ड क्रमांक 7 के पास लुगों की नजर नहर में तैर रहे शव पर पड़ी। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही रतनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालवाकर कब्जे में लिया। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक को पहचान 65 वर्षीय कनक कुमार राज के रूप में हुई है, जो सांघीपारा क्षेत्र के निवासी थे। बताया जा रहा है कि वे रविवार से लापता थे और परिवार लगातार उनकी तलाश कर रहे थे। इसी बीच मंगलवार को उनका शव नहर में मिला। फिहाल मीत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले को हर पहलू से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

पीएससी 2003 भर्ती घोटाले में नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत में बुलाए गए पक्षकार

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित पीएससी 2003 भर्ती घोटाले में एक बार फिर नया घटनाक्रम सामने आया है। मामले को मुख्य याचिकाकर्ता वर्षा डोंगरे और अन्य संबंधित पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। यह मामला वर्ष 2003 की राज्य लोक सेवा आयोग भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और चयन में गड़बड़ी से जुड़ा है। वर्षा डोंगरे ने वर्ष 2006 में इस भर्ती को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले को सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 में अपने फैसले में चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अंकों की हेराफेरी को सही माना था। कोर्ट ने राज्य सरकार को चयन सूची संशोधित कर नई सूची जारी करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के फैसले को चंदन त्रिपाठी सहित अन्य चयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। तब से यह मामला शीर्ष अदालत में लंबित है। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने के प्रयास के तहत विशेष लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसके लिए वर्षा डोंगरे, राज्य सरकार और अन्य पक्षकारों को मुंगेली एवं कबीरधाम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। याचिकाकर्ता वर्षा डोंगरे का कहना है कि हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया था और राज्य सरकार को उस आदेश का पालन करना चाहिए था। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले में संप्रज्ञीत की कोई संभावना नहीं है और अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट से ही होना चाहिए।

अंबिकापुर में विद्युत व्यवस्था सुधार को लेकर महापौर मंजूषा भगत ने ली समीक्षा बैठक.....

अंडरग्राउंड विद्युतीकरण, नए ट्रांसफॉर्मर, क्षतिग्रस्त पोल-केबल बदलने एवं नए विद्युत उपकेंद्र स्थापना को लेकर अधिकारियों को दिशानिर्देश

अंबिकापुर। आज दिनांक 12/5/2026 को अंबिकापुर महापौर श्रीमती मंजूषा भगत द्वारा विद्युत व्यवस्था के संबंध में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई गई। बैठक में नवीन विद्युत पोल लगाने, क्षतिग्रस्त ट्टाने, क्षतिग्रस्त केबल बदलने, ट्रांसफॉर्मर शिफ्टिंग, पोल शिफ्टिंग के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। गांधी चौक से महामाया चौक, सदर रोड व

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर में

नवगठित जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी एवं जन भागीदारी के सभी सदस्यों का प्रथम परिचयात्मक बैठक एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन

अंबिकापुर//आज महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में नगर निगम अंबिकापुर की महापौर श्रीमती मंजूषा भगत की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ किया गया। इसके पश्चात महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अनिल कुमार सिन्हा ने सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। अपने स्वागत उद्बोधन में प्राचार्य प्रो. सिन्हा ने बताया कि वर्ष 1960 में स्थापित यह महाविद्यालय सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा एवं एकमात्र स्वशासी महाविद्यालय है, जहां लगभग 6,000 नियमित विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती छात्र संख्या एवं समय की आवश्यकताओं के अनुरूप महाविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ शैक्षिक नवाचारों के क्रियान्वयन की आवश्यकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनभागीदारी समिति के सहयोग से महाविद्यालय में बेहतर संसाधन एवं सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी। जनभागीदारी समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष एवं नगर निगम पार्षद श्री मनोज



गुप्ता ने कहा कि लंबे समय से समिति के अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण महाविद्यालय के विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे। अब सभी बाधाओं को दूर कर महाविद्यालय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य महाविद्यालय को प्रदेश ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में स्थापित करना है तथा

विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वे स्वयं इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं, इसलिए संस्थान के विकास से उनका विशेष भावनात्मक जुड़ाव है। मुख्य अतिथि महापौर श्रीमती मंजूषा भगत ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह महाविद्यालय अंबिकापुर शहर का गौरव है। इस संस्थान का

गौरवशाली इतिहास रहा है और यहां से शिक्षा प्राप्त कर अनेक व्यक्तियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने नवगठित जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए महाविद्यालय के विकास के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर उपस्थित नगर निगम के पार्षद श्री मनीष सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि यह महाविद्यालय संभाग उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र है और विद्यार्थियों को पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम में जनभागीदारी समिति के सदस्य श्री दीपक यादव, श्री दीपकर, श्री मनोज सोनी, श्री प्रभात विश्वास, श्री अनोश सिंह, श्री अविनाश मंडल, श्री रामप्रवेश पांडे, श्रीमती सरस्वती यादव एवं सुश्री इंदु नेताम उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त भाजपा जिला महामंत्री श्री विनोद कर्ष, पूर्व पार्षद श्री करताराम गुप्ता, श्री पंकज गुप्ता एवं श्रीमती नीलम राजवाड़े भी विशेष रूप से उपस्थित थे। समारोह में महाविद्यालय के प्राध्यापक, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

नेशनल हाइवे-130 स्थित कुंवरपुर मोड़ पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर 40 फिट खाई में जा गिरी

अंबिकापुर। बिलासपुर मुख्यमार्ग पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है एक ओर जहाँ कल एक कार ने एक व्यक्ति को बचते हुए एक खड़ी बाइक को टोक मार दी तो वहीं स्थानीय कुंवरपुर बांध मोड़ के पास एक तेज रफ्तार कार आज सुबह 40 फिट गड्ढे में जा गिरी। मिली जानकारी के अनुसार अधिपेक पांडेय पिता अजय पांडेय निवासी भदोही उत्तरप्रदेश जो की रायपुर के कबीर नगर में निवासरत है कार से अपने घर जाने निकला था जहाँ तेज रफ्तार होने के कारण कुंवरपुर बांध मोड़ के पास अनियंत्रित होकर 40 फिट गहरे खाई में जा गिरी। इस घटना की सूचना मिलते ही लोगो को भीड़ घटना स्थल पर जमा हो



गई जिसके बाद घायल को बड़ी मशकत के बाद पुलिस और लोगो के सहयोग से बाहर निकाला जा सका। घायल को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लखनपुर लाया गया जहाँ मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। लखनपुर का कुंवरपुर मोड़ आए दिन कई दुर्घटनाओं का गवाह बनता है जहाँ सड़क किनारे कोई बैरिकेट नहीं होने से तेज रफ्तार कार सहित कई वाहन गहरे खाई में गिर जाते हैं जिसके बाद कई बार लोग यहाँ दुर्घटना का शिकार होते हैं।

36 वर्षों पुराने विश्वकर्मा मंदिर पर कार्रवाई के विरोध में उठी आवाज

धार्मिक आस्था से जुड़े मंदिर को अवैध बताने पर क्षेत्रवासियों में आक्रोश

कोरबा। पाली रोड दीपका स्थित लगभग 36 वर्षों पुराने विश्वकर्मा मंदिर को नगर पालिका परिषद दीपका द्वारा कथित अवैध कब्जा बताकर को जा रही कार्रवाई के विरोध में अब क्षेत्रवासियों की आवाज मुखर होने लगी है। ग्राम दीपका निवासी रामप्रवेश शर्मा ने जिला कलेक्टर कोखा को आवेदन सौंपकर मंदिर पर को जा रही कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने एवं मामले को निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। आवेदन में बताया गया है कि विश्वकर्मा मंदिर पिछले कई दशकों से क्षेत्र की धार्मिक

आस्था, सामाजिक एकता एवं जनसहभागिता का प्रमुख केंद्र रहा है। मंदिर में नियमित रूप से पूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक कार्यक्रम एवं जनकल्याणकारी गतिविधियां आयोजित होती रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों एवं समाज के सहयोग से निर्मित यह मंदिर क्षेत्रवासियों की भावनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। रामप्रवेश शर्मा ने आरोप लगाया कि बिना उचित जांच, सीमांकन एवं वैधानिक प्रक्रिया अपनाए मंदिर को अवैध कब्जा घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंदिर को लेकर प्रशासनिक दबाव बनाए जाने से श्रद्धालुओं एवं स्थानीय नागरिकों में भारी चिंत और आक्रोश का माहौल है। उनका कहना है कि वर्षों पुराने धार्मिक स्थल को

राजस्व अमला एक माह में या तो अपने कार्यशैली में सुधार लाएं अन्यथा स्थानान्तरण के लिए तैयार रहें-कलेक्टर.....

राजस्व प्रकरणों में किसी के साथ गलत नहीं होगा, आवेदक चिंता नहीं करें

जनगणना कार्य में बढ़-चढ़ कर भाग लेने और प्रगणकों का सहयोग करने ग्रामीणों से अपील

गौरैया पेंडू मरवाही। सुशासन तिहार के अंतर्गत आज मरवाही जनपद के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र के ग्राम पंचायत उपाड़ में जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। इस कलास्टर पंचायत में 17 ग्राम पंचायतों-बगपार, बरौर, बेलझिरिया, चनाडोंगरी, चंगेरी, चिचगोहना, धनीरा, धुमटोला, कछार, कटरा, मनीरा, परासी, तेन्दुमुड़ा, टिकटो, पौडी, करहनी एवं उपाड़ के ग्रामीणों द्वारा विभिन्न मांगों, समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित कुल 711 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 116 आवेदनों का

मौके पर निराकरण किया गया। शेष आवेदनों का निराकरण संबंधित विभागों द्वारा किया जा रहा है। कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन ने विभागवार अधिकारियों और आवेदकों को मंच के पास बुलाकर प्राप्त आवेदनों और की गई कार्रवाई की जानकारी साझा करने कहा। उन्होंने बरौर एवं कटरा के ग्राम वासियों द्वारा पेयजल की समस्या से अवगत कराए जाने पर ग्राम कटरा के मोहल्ल तुरिझिरिया एवं ग्राम बरौर के पुराना बाजार मोहल्ल कंवर पारा मां चतुर्भुजी मंदिर के पीछे नवीन हैंड पंप की स्वीकृति प्रदान करने घोषणा की गई। इसी तरह ग्राम कुम्हारी में पीडीएस हितग्राहियों की सुविधा के लिए नवीन राशन दुकान खोलने की स्वीकृति की घोषणा की गई। कलेक्टर ने एसडीएम को तहसीलदार, आरआई और हल्का पटवारियों की टीम के साथ मंच के पास बुलाकर राजस्व से संबंधित प्राप्त आवेदनों एवं उन पर की गई कार्रवाई की जानकारी से अवगत कराने कहा। एसडीएम द्वारा अधिकार पत्र, फीती नामांतरण, त्रुटि सुधान, जन्म प्रमाण पत्र आदि से संबंधित 117 आवेदन प्राप्त होने

की जानकारी दी गई। कलेक्टर ने सीमांकन के प्रकरणों को एक सप्ताह के भीतर निराकृत करने के साथ ही सभी प्रकरणों को निश्चित समय तय कर निराकृत करने कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जनमानस की सुविधा के लिए समाधान शिविरों का आयोजन कराया जा रहा है। आवेदकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और उन्हें अपने काम के लिए अनावश्यक रूप से भटकना नहीं चाहिए। कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि राजस्व अमला एक माह में या तो अपने कार्यशैली में सुधार लाएं अन्यथा स्थानान्तरण के लिए तैयार रहें। उन्होंने आवेदकों से कहा कि उनके साथ गलत नहीं होगा, वे चिंता नहीं करें। शिविर में आवेदकों की मांग पर विद्युत विभाग द्वारा धरती आबा योजना के तहत विद्युत पोल लगाने, लो वोल्टेज की समस्या दूर करने, कृषि विभाग द्वारा पात्रता की जांच कर रोपा मशीन, किसान सम्मान निधि, मिनी ट्रेक्टर दिलाए, पशुधन विकास विभाग द्वारा उन्नत नस्ल का बकरा दिलाए, मछली पालन विभाग द्वारा मछली बीज प्रदान करने, पंचायत विभाग द्वारा डबरी निर्माण, पेंशन, राशन कार्ड, कुआ निर्माण, आवास, नवीन जांच कार्ड आदि के निर्देश दिए।

नीट पेपर लीक : देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ बड़ा अन्याय

राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल

अंबिकापुर। देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में एक बार फिर पेपर लीक की घटना सामने आना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, चिंताजनक एवं शिक्षा व्यवस्था पर कलंक के समान है। भारत में दूसरी बार नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की गोपनीयता भंग होना यह दर्शाता है कि परीक्षा संचालन और सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियां मौजूद हैं। यह मामला केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के लाखों मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य, उनके सपनों और वर्षों की मेहनत से जुड़ा हुआ है। आजाद सेवा संघ, छत्तीसगढ़ के प्रदेश सचिव रचित मिश्रा ने इस पूरे मामले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने आना बेहद गंभीर विषय है। मीडिया रिपोर्ट्स और जांच एजेंसियों द्वारा सामने आई जानकारी के अनुसार पेपर लीक का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था, जहां कुछ दलालों और संगठित गिरोहों द्वारा मोटी रकम लेकर परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने की कोशिश की गई। यह भी सामने आया कि कुछ परीक्षा केंद्रों एवं संबंधित लोगों की मिलीभगत से परीक्षा की गोपनीयता भंग हुई, जिससे पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस परीक्षा के माध्यम से देश के भविष्य के डॉक्टर चुने जाते हैं, यदि उसी परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो जाए तो यह

एनटीए द्वारा परीक्षा रद्द होना गंभीर लापरवाही का प्रमाण

रचित मिश्रा ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं और अनियमितताओं के बाद एनटीए द्वारा परीक्षा रद्द किया जाना यह साबित करता है कि परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां हुई थीं। परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्रों को मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और भविष्य को लेकर असमंजस का सामना करना पड़ रहा है। जिन विद्यार्थियों ने वर्षों तक मेहनत करके परीक्षा की, उन्हें दोबारा उसी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है, जो बेहद पीड़ादायक स्थिति है। उन्होंने कहा कि सरकार और संबंधित एजेंसियों को केवल परीक्षा रद्द करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पूरे पेपर लीक नेटवर्क का खुलासा कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।



जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं इसमें किसी भी कारण विद्युत कटौती होती है तो शहर की पेयजल सप्लाई व्यवस्था टप हो जाती है इन क्षेत्रों में विद्युत कटौती न हो इसकी व्यवस्था दुरुस्त करने की बात उन्होंने कही। अंडरग्राउंड विद्युतीकरण वाले मार्ग

स्टैंड अंबिकापुर, गृहीरगुरु वार्ड (मठपारा), महामाया पहाड़ (पूटपारा) में भूमि उपलब्ध कराने हेतु सहरौ कार्यपालक यंत्रों ने महापौर जी से आग्रह किया। एवं अजीरमा रेलवे स्टेशन (बीच भंडार के पास) भूमि उपलब्ध हो गई है विद्युत उपकेंद्र स्थापना कार्यालय जल्द प्रारंभ किया जाएगा इस बैठक में विद्युत विभाग के प्रभारी सदस्य श्री मनीष सिंह जी, जल विभाग के प्रभारी श्री जितेंद्र सोनी जी, श्री आकाश गुप्ता जी, श्री विकास गुप्ता जी, विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता शहर श्री जयप्रकाश राजवाड़े, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण श्री आर.सूर्यवंशी, सहायक अभियंता एस.के. गुप्ता, श्री अनेश बंजारे सहायक अभियंता, सहायक अभियंता श्री कैलाश देवांगन, कनिष्ठ अभियंता श्री संगम कुमार पटेल, नगर पालिक निगम के विद्युत व जल प्रभारी श्री प्रशांत खल्लर उपस्थित रहे।



सूर्यास्त की छांव में सुकून की डुबकी

दिनभर की चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली गर्मी के बाद, शाम ढलते ही नदी/तालाब के पानी में राहत ढूँढते बच्चे। गर्म के महीने में सूरज के कड़े तेवर शांत होने पर अंचल के ग्रामीण इलाकों में बच्चे पानी में अठ्ठेलियां कर दिनभर की तपन को मिटा रहे हैं।
फोटो : नाहीद शैख

फर्जी तरीके से राशि आहरण मामले में संलिप्त अधिकारियों पर हो एफआईआर : विनोद चंद्राकर



आहरण किया गया है। बी.एम.ओ. एवं लेखापाल तथा जिला कोषालय के अधिकारी-कर्मचारी एकराय होकर फर्जी तरीके से राशि विभिन्न कर्मचारियों के नाम से निकाली गयी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तुमगांव वर्ष 2019 से डी.डी.ओ. कोड क्र. 11 से स्वतंत्र तौर पर आहरण एवं वितरण का कार्य हो रहा है। तत्कालीन एवं वर्तमान बी.एम.ओ., तत्कालीन एवं निर्वाचित लेखापाल किशोर चौहान, आरती बंजारे द्वारा लोकनाथ चंद्राकर एम.पी.डब्ल्यू. उप स्वास्थ्य केन्द्र पंचरी को 16,31,952 लाख रुपये, सुरेश जांगड़े भुव को 33,98,044 लाख रु. एवं भार्गवसिंह दैवान स्वीपर को 17,19,00 लाख रुपये मूल वेतन के अतिरिक्त कुल राशि 67,48,946 लाख रु. का भ्रूतगत

वेतन देयक में 0 (शून्य) बढ़ाकर किया गया है। आर्थिक गबन में अभी तक केवल लेखापाल किशोर चौहान एवं जिनके खाते में अतिरिक्त वेतन दिया गया है, उन्हें निर्वाचित किया गया है। शेष अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। पूर्व संसदीय सचिव ने कहा कि वेतन देयक विल नज जिला कोषालय में सम्मिलित किया जाता है, तपश्चात् सेक्सन के लिफ्ट एवं ए.टी.ओ. द्वारा निरीक्षण पश्चात् जिला कोषालय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर पास किया जाता है। तपश्चात् कर्मचारियों के खाते में रकम भेजी जाती है। जिला कोषालय के अधिकारी कर्मचारी भी इस फर्जीवाड़े में पूर्णतः संलग्न हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-19 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मैनपुर जिला गरियाबंद में इसी तरह का फर्जी विल सम्मिलित कर जिला कोषालय से राशि आहरण की गयी थी। विधाकक रहते मेरे द्वारा ही विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से जानकारी चाही गयी थी।

इंदिरा मार्केट में 17.35 करोड़ की लागत से बनेगा मल्टीलेवल पार्किंग

298 कार पार्किंग की होगी सुविधा, महापौर बाघमार ने किया स्थल निरीक्षण



दुर्ग/ पुराना बस स्टैंड स्थित इंदिरा मार्केट में 17.35 करोड़ की लागत से बनेगा मल्टीलेवल पार्किंग जिसके लिए महापौर अलका बाघमार ने निगम अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने अधिकारियों एवं संबंधित एजेंसी को निर्दिष्ट करते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य प्रारंभ कर गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए ताकि शहरवासियों को शीघ्र बेहतर पार्किंग सुविधा उपलब्ध हो सके। इस दौरान महापौर अलका बाघमार ने कहा कि शहर में लगातार बढ़ते यातायात एवं बाजार क्षेत्र में पार्किंग की समस्या को देखते हुए मल्टीलेवल पार्किंग परियोजना

अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस परियोजना के पूर्ण होने से इंदिरा मार्केट एवं पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुगम होगी तथा आम नागरिकों, व्यापारियों एवं बाहर से आने वाले लोगों को व्यवस्थित पार्किंग सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार एवं यातायात सुधार के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। मल्टीलेवल पार्किंग बनने से सड़क किनारे अव्यवस्थित पार्किंग पर नियंत्रण लगेगा तथा बाजार क्षेत्र में जाम की स्थिति से भी राहत मिलेगी। प्रस्तावित मल्टीलेवल पार्किंग परियोजना बेसमेंट, ग्राउंड एवं दो फ्लोर सहित निर्मित की जाएगी। परियोजना में लगभग 298 कार पार्किंग क्षमता विकसित की जाएगी। इसके अतिरिक्त परिसर में 11



दुकानों का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे नागरिक सुविधाओं के साथ व्यवसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। 17 करोड़ 35 लाख रुपये की लागत से बनने वाली इस परियोजना की निर्माण अवधि 18 माह निर्धारित की गई है। निरीक्षण के दौरान महापौर ने अधिकारियों को तकनीकी गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर, शेखर चन्द्राकर, ज्ञानेश्वर ताम्रकर, निलेश अग्रवाल, हरिपंक संधव जैन, कार्यालयन अधिकारिता प्रकाश चंद धवानी, राजेन्द्र ढबाले, पंकज साहू, मि. दायर्य साहू, सहित डेप्युटी सहायक निगम के संबंधित अधिकारी, लोककर्म विभाग के कर्मचारी एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

दुर्ग में झारखंड के अंतरराज्यीय अफीम तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़

15 लाख की अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार



दुर्ग। दुर्ग पुलिस को कुम्हारी थाना टीम ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय अफीम तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने झारखंड से छत्तीसगढ़ में अफीम लाकर बेचने वाले दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 15 लाख रुपये मूल्य की अवैध अफीम बरामद की गई है। पुलिस को कुम्हारी और बीएसपी कॉलोनी क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ अफीम की खरीदी-बिक्री की पुख्ता सूचना मिली थी। इस पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले सहीदी राजकेश्वर साहू को हिरासत में लिया। विवेचना के दौरान मोबाइल कॉल डिटेल्स (CDR), आपसी संपर्कों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को खंगालने पर 'एंड टू एंड' (शुरुआत से अंत तक) बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि यह निरोध झारखंड से भारी मात्रा में अफीम लाकर दुर्ग और आसपास के क्षेत्रों में खपाता था। झारखंड के दो आरोपी गिरफ्तार पुलिस ने मामले में संलिप्त मुख्य

आरोपी सुरेंद्र साहू को भी दबोच लिया। फट्टे गए दोनों आरोपी मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं। सुरेंद्र साहू उर्फ सुंदर साहू (32 वर्ष) - निवासी ग्राम लॉजी हुडटोलेली, थाना व जिला गुमला (झारखंड)। राजकेश्वर साहू (32 वर्ष) - निवासी ग्राम लॉजी चौकी, थाना व जिला गुमला (झारखंड)। 15 लाख की अफीम और नगदी जप्त पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध मादक पदार्थ

अफीम: कीमत लगभग 215, लाख रुपये, नगदी रकम: 8,000 (आठ हजार रुपये)। तस्करी में प्रयुक्त मोबाइल फोन। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई, अन्य सहयोगियों की तलाश जारी कुम्हारी पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 89/2026, धारा 18(ख), 27(क) और 29 एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार तस्करों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

नशे के सौदागर शहर में बेखौफ परोस रहे नशा

धमधा नाका सञ्जी मंडी के पास गांजा बेचते आरोपी गिरफ्तार 1 लाख रुपये का माल जप्त



दुर्ग। पुलिस की लगातार सक्रियता के बावजूद नशे का कारोबार थम नहीं रहा है। नशे के सौदागर शहर में बेखौफ नशा परोस रहे हैं। दुर्ग पुलिस ने फिर मुखबिर् की सूचना पर तस्कर को गिरफ्तार किया है। मोहन नगर थाना पुलिस ने धमधा नाका सञ्जी मंडी के पास अवैध रूप से गांजा बेचने की गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से दो किलोग्राम से अधिक गांजा और नगदी रकम जप्त की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 12 मई को मोहन नगर पुलिस को मुखबिर् से सूचना मिली थी कि सञ्जी मंडी धमधा नाका के पास एक युवक नशीला पदार्थ लेकर ग्राहक की तलाश कर रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया। टीम ने बतौर गए स्थान पर पहुंचकर चेचबंदी की और सहीदी को धर दबोचा। आरोपी के पास से 2 किलो गांजा बरामद हुआ। पुछताछ में आरोपी ने अवैध

लाभ कमाने के उद्देश्य से गांजा बेचना स्वीकार किया। आरोपी की पहचान विकास यादव उर्फ लालस (19 वर्ष), निवासी ग्रीन चौक दुर्ग के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2.064 किलोग्राम अवैध गांजा 740 रुपये नगद, बिक्री रकम जप्त किया है जिसकी कीमत लगभग 1,00,740 रुपये आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी विकास यादव के खिलाफ अपराध क्रमांक 323/2026, धारा 20(ख) और 27(क) एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

खुर्सीपार में समर कैंप का भव्य आगाज; खिलाड़ियों ने खेल भावना की शपथ लेकर उड़ाए गुब्बारे, सुमित सिंह ने किया उद्घाटन



भिलाई/दुर्ग। खेल प्रतिभाओं को निखारने और बच्चों को छुट्टियों में खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए खुर्सीपार के श्रीराम चौक ग्राउंड में भव्य 'समर कैंप' (ग्रीष्मकालीन शिविर) की शुरुआत हुई। 10 मई को सुबह सात बजे आयोजित इस उद्घाटन समारोह का नेतृत्व खेल प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुमित सिंह के दिशा-निर्देश में किया गया। कई क्षेत्रों से पहुंचे सैकड़ों खिलाड़ी- इस समर कैंप को लेकर स्थानीय बच्चों और युवाओं में भारी

उत्साह देखा जा रहा है। कैंप के पहले ही दिन खुर्सीपार, छवनी, बैकुंठ धाम, जवाहर नगर और सेक्टर-1 सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उद्घाटन के दौरान मैदान खेल के रंग में रंगा नजर आया। इन खेलों का मिलेगा प्रशिक्षण- आयोजकों ने बताया कि इस शिविर में बच्चों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने और खेल की बारीकियां सिखाने के लिए कई विधाओं को शामिल किया गया है। कैंप के दौरान अनुभवी कोच द्वारा

खिलाड़ियों को क्रिकेट, योग, कराटे, बैडमिंटन, बॉक्सिंग और वॉलीबॉल का निर्वाचित प्रशिक्षण दिया जाएगा। शपथ और गुब्बारे उड़ाकर शुरुआत- समारोह की शुरुआत में सभी विधाओं के खिलाड़ियों ने पूरी खेल भावना और अनुशासन के साथ खेलने की शपथ ली। इसके बाद मुख्य अतिथियों और बच्चों ने हवा में रंग- बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर कैंप का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान उपस्थित पालकों ने भी खेल प्रकोष्ठ के इस प्रयास

की सराहना की। वरिष्ठ जन रहे उपस्थित- इस गरिमामय खेल आयोजन के अवसर पर खेल प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुमित सिंह के साथ गुड्डु खान, डी. कामराज, अजहर अली, शंकर राव और माधव विशेष रूप से उपस्थित रहे। खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए मुख्य प्रशिक्षक (कोच) नीरज चौधरी, जितेंद्र, चंदन शर्मा, वी.पी. सिंह और विमल भी मैदान में डटे रहे। पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन नाग सर द्वारा किया गया।

पाटन के बेलौदी में उल्टी-दस्त का प्रकोप; स्वास्थ्य विभाग ने संभाला मोर्चा, मिले 7 नए मरीज

दुर्ग। पाटन विकासखण्ड के ग्राम बेलौदी में उल्टी-दस्त (डायरिया) फैलने की सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रभावित इलाके में डेरा डाल दिया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (एसडब्ल्यू) डॉ. मनोज दानी के निर्देश पर जिला सर्वलैस अधिकारी डॉ. सी.बी.एस. बंजारे और पाटन बीएसओ डॉ. भुनेश्वर कटौतिया समेत विशेषज्ञों की टीम ने बुधवार को गांव का आंचक दौरा किया। 180 घरों का सर्वे, अब तक 56 प्रभावितस्वास्थ्य अमले द्वारा प्रभावित क्षेत्र में लगातार एक्टिव सर्वलैस और घर-घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। बुधवार को टीम ने कुल 180 घरों की जांच की, जिसमें उल्टी-दस्त के 7 नए मरीजों की पहचान हुई। अधिकारियों के मुताबिक, बीते 11 मई से अब तक गांव में कुल 56 मरीज सामने आ चुके हैं। 11 मरीज अस्पतालों में भर्ती, स्थिति नियंत्रण में है। बाकी मरीजों की जांच यह है कि संक्रमण से



किसी भी मरीज को मौत नहीं हुई है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। कुल मरीजों में से 11 का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इनमें से 4 मरीज सीएससी पाटन, 2 जिला अस्पताल, 3 सेल्टु अस्पताल, 1 आस्था अस्पताल और 1 मरीज महिमा अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी बचे 45 मरीजों का डॉक्टरों की निगरानी में घर पर ही इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ग्रामीणों से अपील- हमेशा पानी को अच्छी तरह उबाल कर ही पिएं। बासी या सड़े-गले फल और सब्जियों का सेवन बिल्कुल न करें। उल्टी या दस्त के लक्षण दिखते ही तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। बिना डॉक्टरों की सलाह के कोई भी दवा खुद से न लें।